• वर्ष-2
• अंक-284
रायपुर, गुरुवार 20 जुलाई 2023
• पृष्ठ-6
• मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

मानसून सत्र में 31 विधेयकों पर होंगे विचार

सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार

नई दिल्ली। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। इस सूची में सबसे ऊपर दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश है। सरकार कोशिश करेगी कि इसे दोनों सदनों से जल्द से जल्द से पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। इस बीच संसद के मानसून सत्र से पहले एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक से पहले सरकार ने सभी दलों के साथ भी अहम बैठक की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सभी पार्टियां मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रही थी, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि नाम बदलने से लोग नहीं बदल जाएंगे। लोग तो वही हैं, यह तो वह बात है कि पुरानी वाइन और नई बोतल।

मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो सत्र शुरू होने से पहले प्रथागत है। इसका उद्देश्य सभी दलों को एक साथ लाना और उनकी चिंताओं को दूर करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने 39 सदस्य दलों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। दूसरी ओर, 26 दलों वाला विपक्ष पहले से ही बेंगलुरु में दो दिवसीय बैठक में लगा हुआ था। इस बैठक का उद्देश्य एक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाना था और जिसने

खुद को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन भी कहा।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को इसी तरह की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन कई दलों के नेताओं की अनुपलब्धता के कारण इसे टाल दिया गया है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया नया संसद भवन, आगामी मानसून सत्र का स्थान होगा। 14 जून को एचटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, संसद में अधिकांश राजनीतिक दलों को कार्यालय आवंटित कर दिए गए हैं और संबंधित विभागों को नई सुविधा में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।

संसद सत्र हंगामेदार रहने के आसार

इस साल विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा और विपक्षी पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, ऐसे में संसद सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों के अलावा मणिपुर संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला सत्र भी लगातार विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया था।

केंद्र मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार

केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मानसून सत्र के लिए विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की गई।

इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग

कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान सरकार से चीन से लगने वाली सीमा पर स्थिति, महंगाई, ओडिशा रेल हादसे, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराने की मांग की है। हम दिल्ली इसलिए आए हैं कि सदन में चर्चा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं।

11 अगस्त तक चलेगा सत्र

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। जानकारी के मुताबिक, मानसून सत्र 11 अगस्त तक चल सकता है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं।

कांग्रेस के सख्त तेवर

वैसे तो यह संसद का मॉनसून सत्र है लेकिन इस दौरान राजनीतिक गर्मी बढ़े रहने के आसार हैं। दरअसल कांग्रेस ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से मणिपुर की स्थिति एवं ओडिशा रेल हादसे जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करते हुए कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की।'' उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो।''

चौधरी ने कहा, मैंने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उन सभी मुद्दों को उठाया जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक में भी मैंने इन मुद्दों को उठाया। हमारी मांग है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।'' लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा, दो महीने गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) चुप हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें संसद में बयान देना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए।'' उन्होंने कहा, हम कल कार्यस्थगन प्रस्ताव (चर्चा कराने के लिए) लाना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर की स्थिति खराब हो रही है।'' चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को हमारे दिल की बात सुननी चाहिए और विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने चीन से लगने वाली सीमा पर स्थिति, महंगाई, ओडिशा रेल हादसे, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराने की मांग की है।

इन दिनों

पार्टी बदली, गठबंधन बदला, नाम- नारा बदला

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियों का बिगुल बज गया है। नेताओं ने पार्टियां बदलना शुरू कर दिया है, पार्टियों ने गठबंधन बदलना शुरू कर दिया है और गठबंधनों ने नाम और नारे बदलना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2004 में जिस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानि यूपीए की स्थापना की थी उसका नाम बदल कर इंडिया कर दिया गया है। इस इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस विरोधी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हो गयी हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 26 तक पहुँच गयी है तो दूसरी और देश में पहली बार गठबंधन सरकार के प्रयोग को सफल बनाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 39 तक पहुँच गयी है। अब, आगामी लोकसभा चुनावों को एनडीए बनाम इंडिया करार दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन वाले टैगलाइन दे रहे हैं- जीतेगा भारत तो दूसरी ओर एनडीए कह रहा है कि आजादी के शताब्दी वर्ष तक हमें विकसित, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनाना है। यानि एक तरफ सिर्फ इंडिया है तो दूसरी ओर विकसित और आत्मनिर्भर भारत। आप जरा गौर करेंगे तो यह भी पाएंगे कि इस समय नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों की जोरदार तरीके से रि-ब्रांडिंग हो रही है, यानि आपको नये कलेवर में पुराना माल ही परोसा जा रहा है। जमाना बदला है तो राजनीतिक दलों ने भी अपना अंदाज बदला है इसीलिए आपको आजकल नेता बाइक ठीक करते, खेत में धान रोपते, गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते, गरीब के बच्चों को गोद में उठाते, ढाबे पर खाना खाते और मेट्रो ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधनों में आम यात्रियों के साथ यात्रा करते हुए दिख जाएंगे। आलीशान जिंदगी जीने वाले सभी नेताओं का प्रयास है कि अपने को गरीब और वंचितों के बीच का ही दिखाया जाये ताकि चुनावों के समय मतदाता ध्यान रखे कि अमुक नेता तो हमारे जैसा ही है इसलिए यदि उसे सत्ता मिली तो वह हमारा ध्यान रखेगा। जरा बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक को देखिये। उस बैठक में देश के गरीबों, वंचितों और शोषितों के हित में मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। लेकिन गरीबों, वंचितों, शोषितों के बारे में चिंता करने के लिए बेंगलुरु आने के लिए सभी नेताओं ने चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया। एनडीए की बैठक को देखेंगे तो यह भी राष्ट्रीय राजधानी के एक बड़े पांच सितारा होटल में हुई। इन बैठकों का खर्च भी लाखों रुपए में आया होगा। बात यदि पार्टियों और गठबंधनों के नये रंग-रूप की करें तो इससे भले इन नेताओं, पार्टियों और गठबंधनों को लाभ हो जाये लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं बदलने वाला है। क्योंकि पार्टी या गठबंधन का नाम भले बदल जाये नेता तो वही रहेंगे। और जब नेता वही रहेंगे तो उनकी नीयत भी वही रहेगी। जब नीयत वही रहेगी तो देश की नियति भी वही रहेगी।

कर्मचारी हित में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, 4 % डीए में वृद्धि

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने शासकीय कर्मियों के लिए 4 प्रतिशत डीए वृद्धि के साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने शासकीय कर्मियों के अतिरिक्त संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी सहित सभी वर्गों के कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की घोषणा की। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हो चुकी है। 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37000 संविदा कर्मियों के

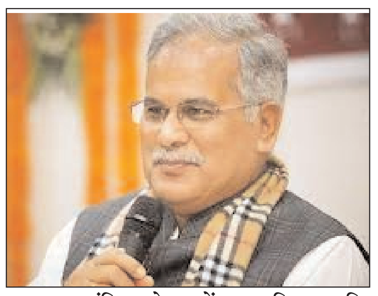

एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

जार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपए की तथा 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

प्रमुख समाचार

मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब ट्विटर पर 90 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिसने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेताओं में से एक बना दिया है। इस बीच, पीएम

मोदी ट्विटर पर 2,589 लोगों को फॉलो करते हैं। पीएम मोदी ने साल 2009 में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया था। उस दौरान वे गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। ट्विटर ज्वाइन करने के महज एक साल के भीतर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। जुलाई 2020 में पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी छह करोड़ थी और एक साल बाद जुलाई 2021 में फॉलोअर्स की संख्या में एक करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ। आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले ट्विटर बॉस एलन मस्क ने भी इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। मस्क स्वयं 195 व्यक्तियों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, जिनमें से एक पीएम मोदी भी हैं।

उद्धव और अजित पवार की मुलाकात से चढ़ा सियासी पारा

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई में उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की। इस दौरान आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पहली बार अपने पूर्व सहयोगी अजित पवार से मुलाकात की है। हालांकि, इसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। अलग-अलग तरह की चर्चाए शुरू हो गई है। राज्य विधान परिषद के सदस्य ठाकरे थोड़े समय के लिए सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। उनकी एक समय की पार्टी सहयोगी तथा उप सभापति नीलम गोरे के शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंद्वी शिवसेना में शामिल होने के बाद वह पहली बार सदन में पहुंचे थे। वित्त मंत्री पवार से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा कि मैंने उनसे राज्य और लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए कहा। ठाकरे ने कहा, मुझे विश्वास है कि राज्य के लोगों को सहायता मिलेगी क्योंकि खजाने की चाबियां उनके पास हैं।उन्होंने पवार के साथ उनके मंत्रिमंडल में काम किया है और उनकी कार्यशैली को जानते हैं। पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में पवार ठाकरे के डिप्टी थे।

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित तौर पर फर्जी सबूत गढ़ने की एफआईआर के सिलसिले में बुधवार को तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दे

दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जमानत के दौरान सीतलवाड का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वह गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी और उन गवाहों से दूर रहेगी जो ज्यादातर गुजरात में हैं। इस स्थिति में, उन्हें इस शर्त का उल्लंघन करते हुए पाया गया, अदालत ने गुजरात पुलिस को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर जमानत रद्द करने की अनुमति दी। पिछले साल 2 सितंबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें इस आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि वह एक महिला हैं और मामला 2002 से संबंधित है जहां अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ये शर्तें आज भी प्रासंगिक पाई गईं और इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत पर बाहर रहने का निर्देश दिया।

चमौली में ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की मौत

उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर आज एक ट्रांसफार्मर फट गया, जिससे पंद्रह लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना

की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दुखद घटना में बुधवार को चमोली जिले में एक ट्रांसफार्मर में विस्फोट के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, हादसा अलकनंदा नदी के किनारे हुआ। मीडिया से बात करते हुए चमोली के एसपी परमेंद्र डोभाल ने घटना की पुष्टि की और कहा कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों में पीपलकोटी का एक चौकी प्रभारी भी शामिल है। यह हादसा अलकनंदा नदी के किनारे बने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट प्रवाह के कारण हुआ। इससे पहले खबर आई थी कि इस घटना में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। एडीजी वी मुरुगेसन ने कहा कि एक सब-इंस्पेक्टर और 3 होम गार्ड सहित 15 लोग बिजली की चपेट में आ गए।

पुंछ में मुठभेड़ में मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तानी थे

जम्मू। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में मंगलवार सुबह भारतीय सेना और जेकेपी के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप द्वारा मारे गए चार आतंकवादियों के पास से बरामद पहचान पत्रों से पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) समूह के सभी चार जिहादी पाकिस्तानी नागरिक थे। नियंत्रण रेखा के पास राजौरी-पुंछ सेक्टर के सिंदाराह गांव में भारतीय बलों ने भारी हथियारों से लैस चार आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए जिहादियों के पास से बरामद दस्तावेजों के अनुसार, उनकी पहचान महमूद अहमद, अब्दुल हमीद, मोहम्मद शरीफ हैं और चौथे का नाम अज्ञात है, सिवाय इसके कि वह एलओसी पार करने के बाद मुठभेड़ स्थल के ठीक पार अधिकृत कश्मीर के खुर्शीदाबाद का रहने वाला है। चारों साजिद जट्ट के नेतृत्व वाले 12 लश्कर आतंकवादियों के एक समूह से संबंधित हैं, जो पीओके में कोटली और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार सियालकोट के बीच काम करते हैं। वे सभी लगभग 23-25 ??वर्ष की आयु के हैं और जिहाद के कट्टर अनुभवी हैं और पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर लश्कर के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में डूरंड रेखा के पार काम कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार 12 सदस्यीय समूह पिछले 18 महीनों से राजौरी-पुंछ सेक्टर में काम कर रहा है।

अलग हैं विस्तार और गठजोड़...भारतीय राजनीति की दिशा भी बदली

अभय कुमार दुबे

आज मैं पाठकों के सामने दो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों की राय रखूंगा। इनमें पहले हैं प्रणब सामंत, और दूसरे हैं आर। जगन्नाथन। प्रणब सामंत ने हाल ही में एक लेख के जरिये यह बताने की कोशिश की है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से गठजोड़ राजनीति के तौर-तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है।

इस तरह उसने राजनीति की दिशा भी बदली है, और साथ-साथ अपना सांगठनिक विस्तार भी करके दिखाया है। प्रणब हमें एक ऐसी सूचना देते हैं जो वैसे तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन उसका वह राजनीतिक सार हमें नहीं दिख रहा है जो वे दिखाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भाजपा ने पंजाब में सुनील जाखड़ को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। अभी दो साल पहले जाखड़ पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका परिवार भी कांग्रेसी ही रहा है। उसी तरह आंध्र प्रदेश में भाजपा ने डी। पुरंदेश्वरी को अपना अध्यक्ष बनाया है जो कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष जनता दल (एकीकृत) के खाते से आया है, और असम में असम गण परिषद की कतारों से। यानी, वे दिन चले गए हैं जब भाजपा केवल संघ के प्रचारकों को ही संगठन में बड़े पद देती थी, या उन लोगों को महत्व मिलता था जो किसी न किसी प्रकार हिंदुत्ववादी विचारों के नुमाइंदे रहे हैं।

भाजपा के आलोचक कहते हैं कि यह भाजपा के कांग्रेसीकरण का सबूत है, लेकिन

प्रणब का दावा है कि भाजपा अपने विस्तार के लिए लीडरशिप आधारित भर्ती में जुटी हुई है। असम और मणिपुर के मुख्यमंत्री भी पहले कांग्रेसी थे। पंजाब से अमरिंदर सिंह और आंध्र से किरण कुमार रेड्डी को लेकर उनके कांग्रेसी अतीत की परवाह किए बिना भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। उसका संदेश साफ है कि नेता किसी भी पार्टी का क्यों न हो, अगर वह भाजपा के लिए उपयोगी है तो उसकी हैसियत के मुताबिक उसे अहमियत दी जाएगी। नए नेताओं की इसी तरह की भर्ती के साथ जुड़ा हुआ है यह इरादा कि भाजपा एक अलग तरह से गठजोड़ बनाने की इच्छुक है। वह पिछले एक-डेढ़ साल से अपने खिलाफ खड़े हुए गठजोड़ों से छोटे-छोटे घटक दलों को अपनी ओर खींच रही है। साथ ही जहां पार्टियां बड़ी-बड़ी हैं और उनके नेता भाजपा की तरफ झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, वहां वह उन पार्टियां को तोड़ देने में लगी हुई है।

अगर प्रणब ने भाजपा की रणनीति का एक आख्यान पेश किया है, तो आर। जगन्नाथन का ध्यान विपक्ष पर केंद्रित है। वे यह मानते हैं कि विपक्ष के एकता-प्रयासों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस दलील को पुष्ट करने के लिए वे एक कहानी सुनाते हैं। एक शिकारी और उसका कुत्ता शिकार करने के लिए हिरण का पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर भी हिरण भाग निकला। इस पर शिकारी ने अपने कुत्ते को ताना देते हुए पूछा कि हिरण उससे ज्यादा तेज क्यों साबित हुआ। इस पर कुत्ते का जवाब था कि वह तो अपने मालिक के उस मजे के लिए दौड़ रहा था जो उसे शिकार करने में आता है। पर हिरण तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए उसकी रफ्तार का कोई ठिकाना नहीं था। जगन्नाथन इस कहानी द्वारा बताना चाहते हैं कि विपक्ष के पास अपनी भाजपा विरोधी एकता के लिए कहीं अधिक मजबूत कारण हैं, उन राजनीतिक शक्तियों के बनिस्बत जो फौरी फायदों के लिए अपनी पार्टियां तोड़कर भाजपा से जुड़ गई हैं। जगन्नाथन और प्रणब के विश्लेषण में अंतर है। दोनों ही भाजपा के दक्षिणपंथी प्रोजेक्ट के प्रवक्ता। लेकिन प्रणब कह रहे हैं कि इन गैर-भाजपा शक्तियों को दूरगामी मकसदों से अपनी ओर ला रही है। जगन्नाथन कह रहे हैं कि उसका मकसद अल्पकालीन है। लेकिन इस अंतर के बावजूद दोनों कम से कम यह तो कह ही रहे हैं कि भाजपा कहां स्वयं को मजबूत कर रही है, और कहां उससे लड़ने वाली ताकतें अपनी पेशबंदी कर रही हैं।

इन दो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों की राय पेश करने का मेरा मकसद यह दिखाना है कि राजनीति की समीक्षा के लिए वामपंथी मुहावरे में सोचना ही काफी नहीं है। दक्षिणपंथी पूरी परिस्थिति को कैसे देख-समझ रहे हैं, इस पर निगाह रखना भी जरूरी है। इसी तरह मेरे जैसे समीक्षकों को यह भी देखना चाहिए कि यह बुद्धिजीवी कब भाजपा की आलोचना करते हैं, यानी वे कौन से मुकाम होते हैं, जब उन्हें भाजपा के काम पसंद नहीं आते।

धरती हमारी मां है इसीलिए निर्माण कार्य का शुभारंभ मां के आशीर्वाद से की जाती है : रंजना

धमतरी। धमतरी शहर से लगे गांव डोड़की जहा पर लगभग 32 साल पहले बने कलामंच जो की अत्यंत ही जर्जर हालत में है उसके जगह पर नए सांस्कृतिक कलामंच की मांग निरंतर ग्राम वासियो के द्वारा की जाती रही है, क्योंकि उक्त स्थल पर सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम आयोजित की जाती रही है किंतु जर्जर होने के कारण मंच के बाहर कार्यक्रम करने के लिए ग्रामवासी विवश थे, जिसको विधायक रंजना साहू को अवगत कराए जाने पर विधायक ने अपने विधानसभा विकाश निधि से स्वीकृति देते हुवे ग्रामवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किए, एवं क्षेत्र के माननीय सांसद चुन्नीलाल साहू जी की अनुशंसा से स्वीकृति सिन्हा समाज भवन में आहता शेड निर्माण दिया गया है, जिसका भूमिपूजन कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों की उपस्तिथि में विधायक के करकमलों से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वागत उद्बोधन में ग्रामीण कोषाध्यक्ष दिलीप सिन्हा ने बहुप्रतीक्षित सांस्कृतिक कला में निर्माण की स्वीकृति दिलाने पर विधायक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त अतिथियों का ग्रामवासियों की ओर स्वागत किए और गांव के विकास के विषय में जानकारी दिए। अतिथि उद्बोधन में विधायक रंजना साहू ने कहा कि किसी भी कार्य को शुभारंभ करने के लिए मां का आशीर्वाद होना आवश्यक है, और धरती हमारी मां है इसीलिए निर्माण कार्य का शुभारंभ मां के आशीर्वाद से धरती मां की पूजा अर्चना कर कार्य को शुभारंभ की जाती है। निर्माण कार्यों की बधाई देते हुवे विधायक ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी गांव वालो को दिए साथ सांसद जी की ओर से समस्त ग्रामवासियों को बधाई दिए। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत सरपंच प्रदीप सिन्हा ने कहा कि गांव व शहर में विकाश कार्यों की नवनिर्माण आधारशिला रख कर जनता के बीच सबसे लोकप्रिय विधायक रंजना साहू है नारी शक्ति की पहचान जिन्होंने धमतरी की जनता की आवाज बनकर विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न लगाकर जनहित मुद्दो को रखी और उनकी सक्रियता का परिणाम है की उसको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा पटल में उत्कृष्ट विधायक चुना गया, यह हम सभी के लिए गौरांवित होने की बात है। जनपद सदस्य जागेश्वरी साहू ने समस्त ग्रामवासियों को रंगमंच निर्माण कार्य की बधाई दिए और गांव के विकाश के लिए सभी को सजग रह कर काम करने की बात कही। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जनपद अध्यक्ष मनीषा साहू, भाजपा बुथ अध्यक्ष राजकुमार सिन्हा, उपसरपंच दिनेश्वरी बघेल, ग्रामीण संरक्षक मनमोहन सिन्हा, ग्रामीण अध्यक्ष अश्वनी सिन्हा, पूर्व जनपद सदस्य चमन साहू, डॉ नारायण सिन्हा, रामकुमार सिन्हा, पंच गणों में ईश्वरलाल सिन्हा, मुरार बांधे, दाऊलाल सिन्हा, कुलेश्वर सिन्हा, मनीष ध्रुव, नोमेश, अमरिका, जमवंतीन ध्रुव, हिरौंदीबाई, खिमेश्वरी, रुखमणी, निर्मला यादव सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

भाजपा सरकार नहीं बनी तो राजनीति से सन्यास ले लेंगे ननकीराम कंवर

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कद्दावर आदिवासी नेता और कोरबा जिले की रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ननकीराम कंवर ; 80 वर्ष ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

विधायक ननकीराम कंवर अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 6 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ननकीराम कंवर स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं और अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी वर्ग से होने के बावजूद वह शराब के प्रखर विरोधी है। प्रदेश में गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासियों को शराब के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान चला रखा था। उनके इस अभियान का ही परिणाम था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने क्रमश: शराबबंदी करने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश में शराब दुकानों को बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ था और कि दुकानें बंद की गई थीं। वह ननकीराम कंवर ही थे जिनके खाद्य मंत्री रहते चावल में कनकी की मिलावट पर प्रभावी रोक लगी थी। उस समय तो एक नारा ही बन गया था. ष् जब तक खाद्य मंत्री है ननकीए तब तक चावल में नहीं चलेगा कनकी। ननकीराम कंवर के नाम पर ही मध्यप्रदेश में संपूर्ण कृषि उत्पादन का अब तक का सर्वश्रेष्ठ 27: उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज है।

विधायक ननकीराम कंवर को नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या घोषित कराने का भी श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2008 से 2013 तक जब कंवर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री थे तब इनके ही प्रस्ताव पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या घोषित किया था और नक्सलवाद उन्मूलन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। राजनीति में 50 वर्षों से भी अधिक का प्रदीर्घ अनुभव रखने वाले ननकीराम कंवर मतदाताओं का रुझान भांपने में माहिर हैं। वर्ष 2018 के चुनाव से पहले ही पार्टी प्लेटफार्म में इन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार की जानकारी रख दी थी। ननकीराम कंवर ने कहा देखिए मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में यह अनुभव कहता है कि जितना हमने काम किया है यह सरकार काम कर रही है इस आधार पर इस समय 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि इस सरकार में हर जगह करप्शन लोगों का काम नहीं होना भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैंने तो विधानसभा में भी बोला था कि मुख्यमंत्री इतना भ्रष्टाचार मत करो ।

नक्सली इलाके में आईईडी ब्लास्ट होने की आशंका, सड़क पर हुए गड्ढे से मचा हड़कंप

बीजापुर। बीजापुर जिले में लगातार बारिश हो रही है। इसी बीच बुधवार सुबह कुटरू फरसेगढ़ इलाके में सोमनपल्ली मार्ग पर ब्लास्ट होने की खबर मिली है। धमाके से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया है। घटना में किसी भी तरह की जनहानि की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने अभी घटना की पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजापुर जिले के फरसेगढ़ व सोमनपल्ली मार्ग पर चलीसोनकली नाला पुलिया के पास बुधवार की सुबह करीब 9 बजे नक्सलियों द्वारा प्लांट कर रखा गया आईईडी (ढ्ढश्वष्ठ) ब्लास्ट हो गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारी बारिश होने के चलते स्विच स्पार्क हो गया और बिना कमांड के ही ढ्ढश्वष्ठ फट गया। इस विस्फोट से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया है। हालांकि पुलिस ने विस्फोट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस ने बताया है कि सोमनपल्ली के चलीसोनकली नाला के पास सड़क पर गड्ढा होने की जानकारी उन्हें मिली है। गड्ढा बारिश की वजह से हुआ है या किसी दूसरे कारण से हुआ है , पुलिस इसकी जानकारी जांच के बाद देने को कह रही है।

नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान के उपर गिरा विशालकाय पेड़

कांकेर। कांकेर ताड़ोकी थाना क्षेत्र कोसरोंडा कैंप में मोर्चे में तैनात एसएसबी जवान के ऊपर एक विशालकाय पेड़ गिर गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जवान की हालात गंभीर बनी हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब जवान मचान पर चड़कर ड्यूटी कर रहे थे, अचानक पेड़ गिरने से वह वहां से भाग नहीं सके और उसके चपेट में आ गए।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोसरोंडा कैंप में पदस्थ एसएसबी 33 बटालियन के आरक्षक संतोष कुमार मोर्चे पर तैनात थे और मचान पर चढ़कर ड्यूटी कर रहे थे। अचानक इसी दौरान एक विशालकाय पेड़ उसके ऊपर गिर गया। जिससे वह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में पिछले दो दिनों से लगातार बारीश हो रही है जिसके कारण पेड़ के आसपास की जमीन धंस गई थी।

रवि ठाकुर का निष्कासन हुआ रद्द कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

नगरी। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी के अध्यक्ष रवि ठाकुर का निष्कासन रद्द कर दिया गया है विगत 10 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी सप्त गिरी उल्का के धमतरी आगमन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष से कहा सुनी के चलते रवि ठाकुर को पार्टी से 6 वर्षों के लिये निष्कासित कर दिया गया था ।रवि ठाकुर द्वारा अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में सदैव कांग्रेस पार्टी के विचार धारा के अनुरूप कार्य करने की बात प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज व प्रदेश महामंत्री रवि घोष सहित अन्य पदाधिकारियों से कहे जाने पर उनका 6 वर्ष का निष्कासन रद्द करते हुए पुन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन में प्रवेश दिया गया है।

पूर्व ब्लाक अध्यक्ष रवि ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी में वापसी पर प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज,आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम, विधानसभा उपाध्यक्ष सन्त नेताम, प्रदेश महामंत्री रवि घोष,प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, जिला संगठन प्रभारी बीरेश ठाकुर, पूर्व विधायक अम्बिका मरकाम, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा,नि:शक्त जन आयोग अध्यक्ष मोहन लालवानी व अन्य नेताओं का आभार माना है। रवि ठाकुर के निष्कासन रद्द होने पर वरिष्ठ कांग्रेसी राम प्रसाद मरकाम,जिला पंचायत सदस्य मीना बंजारे, ब्लाक अध्यक्ष डिहू राम साहू,चांदन बाफ्ना,राजेश साहू, हेमंत देवांगन,गोपी कृष्ण लाहौरिया, भरत निर्मलकर, सचिन भंसाली,नदीम अली,युवा अध्यक्ष सोनू चौहान,छबि ठाकुर, आदित्य ठाकुर, मिलेश्वर साहू, मनोज गुप्ता, पंकज ध्रुव, निश्चल लाहौरिया, पन्ना ध्रुव,भरत लहरे,किशन गजेंद्र,शंकर नेताम, पार्षद सोहन चतुर्वेदी, जितेंद्र ध्रुव, बीरेंद्र निर्मलकर, सलीम मेमन, चुन्नी लाल साहू, सोहेल खान, आशिफ खान, भोलू खान, अकरम खान, ईशु अली, रूपेश साहू ,आत्मा ध्रुव ,पिंकी यदु,आदि ने हर्ष जताया है।

14 लाख का स्ट्रीट लाइट घोटाला मुख्य कार्यपालन अधिकारी पहुंचा जेल

कांकेर। 14.40 लाख रूपए के स्ट्रीट लाइट घोटाले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसकी जांच कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने की थी।

जानकारी के मुताबिक जिला खनिज न्यास निधि अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत योन्दानार में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईट की स्थापना (30 नग) राशि 14.40 लाख रूपये के संबंध में कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृति प्रदाय की गई थी. लेकिन उक्त पंचायत में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिये जाने की अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर के पास पहुंची।

कलेक्टर कांकेर के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांच कराया गया, शिकायत जांच समिति द्वारा जांच में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज न्यास जिला उ. ब. कांकेर द्वारा ग्राम पंचायत बोन्दानार, जनपद पंचायत अंतागढ़ में 30 नग सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई थी परन्तु उक्त पंचायत में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया है और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया है.

उक्त वित्तीय अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा को तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ पी. आर. साहू, तत्कालीन उप अभियंता विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संचालक प्रोपराईटर मेसर्स आर. बी. ड्रीलर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन केशकाल, जिला कोण्डागांव के द्वारा अपराध घटित करना पाया गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

शिक्षकों की हड़ताल से 387 स्कूलों में लटके ताले

कोरबा। छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा के आह्वान पर जिले के एलबी वर्ग के 800 से भी अधिक शिक्षकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से प्राथमिक व मिडिल के 387 स्कूलों के पट बंद रहे। नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर 800 शिक्षकों रायपुर में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। शिक्षकों के अवकाश से स्कूलों अध्यापन कार्य ठप रही। रविवार और सोमवार के अवकाश के तीसरे दिन भी स्कूलों के पट बंद रहे। प्रदेश भर के एलबी वर्ग शिक्षकों में वेतन विसंगति को लेकर निराशा देखी जा रही। नियुक्ति तिथि से वेतन का मापदंड अन्य नियिमति शिक्षकों की तुलना में कम होने से शिक्षकों में असंतोष व्याप्त हैं। इससे पहले भी संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर शिक्षक सात जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे। सरकारी अवकाश के अलावा शिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने स्कूलों में समय के अनुसार पाठ्यक्रम के अध्यापन में प्रगति नहीं आ रही है। मंगलवार को शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश पर जाने की पहले से ही सूचना दे दी थी।

बिजली को लेकर भाजपा ने किया कार्यालय का घेराव

कोरबा। कोरबा जिलान्तर्गत बिजली विभाग की लचर व्यवस्था का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी कोरबा विधानसभा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के तुलसी नगर सब स्टेशन का घेराव किया। भाजपाइयों ने लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती का भी आरोप लगाकर जल्द निराकरण करने की मांग रखी। भाजपा नेताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान बिजली बिल और जबरन अवैध वसूली का भी आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों पर निशाना साधा। स्ट्रीट लाइट की समस्याओं का निराकरण, व्यवसायिक परिसरों के बिजली कनेक्शन के मरम्मत कार्य सहित बिजली विभाग में लंबित समस्त आवेदनों का निराकरण करने की बात रखी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, कोरबा जिला नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, आरपीएस त्यागी, लखन लाल देवांगन, विकास अग्रवाल, सुफ्ल दास, पार्षद सुश्री ऋतु चौरसिया, वैशाली रत्नापारखी, मीना मंजू सिंह, पवन सिन्हा, मनोज मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

संभागायुक्त ने लापरवाह क्लर्क को किया निलंबित

दुर्ग। दुर्ग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर कई तरह की गड़बडियां और लापरवाही पकड़ी। इस दौरान समय से कार्यालय नही आने वाले सहायक ग्रेड 3 को निलंबित कर दिया गया। वहीं अन्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। दाऊ वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति और दुर्ग संभाग के आयुक्त द्वारा समृद्धि बाज़ार के पास स्थित पशु चिकित्सालय दुर्ग का अचानक निरीक्षण किया गया। समय पर नहीं आने के कारण आर के देवांगन सहायक ग्रेड 3 को निलंबित करने संचालक वेटेनरी महाविद्यालय अँजोरा को निर्देशित किया और 8 अन्य अनुपस्थित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने सोनोग्राफी, एक्स रे, ओ पी डी , ओ टी सहित सभी सुविधाओं की जानकारी लिया एवं साफ-सफाई के साथ अस्पताल में व्यवस्था को दुरूस्त रखने कहा।

रेलवे स्टेशन में अजगर निकलने से यात्रियों में दहशत

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन मुख्यालय बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के बीच अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। एक स्टॉल संचालक ने अजगर को पकडऩे का असफल प्रयास भी किया। दरअसल पटरी के किनारे और रेलवे स्टेशन परिसर में मोटे-मोटे चूहों का आतंक है। इन चूहों के लालच में अक्सर रेलवे स्टेशन के आसपास जहरीले सर्प निकलते रहते हैं। बताया जाता है कि इसी क्रम में प्लेटफार्म नंबर 4-5 में एक अजगर चूहों का शिकार करने निकला था। अचानक एक यात्री की नजर अजगर पर पड़ी और इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग अजगर को देखने जुटने लगे, इसी बीच एक स्टॉल संचालक ने हिम्मत करते हुए अजगर को पूंछ से पकडऩे का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद अजगर भी सजग हो गया और प्लेटफार्म को पार कर झाडिय़ों में गुम हो गया। यात्रियों को इसकी सूचना रेलवे अमले को दी, मगर रेलवे अमले से कोई रिस्पांस नहीं मिला।

पार्षद की शह पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से हो रहा था राशन गायब

दुर्ग। खुर्सीपार क्षेत्र के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में औचक छापा मारने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। यहां पिछले 3-4 माह का पूरा कोटा जनता में बिना बांटे ही खत्म हो गया। मामले की शिकायत एक भाजपा पार्षद ने दर्ज कराई थी, इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर यह औचक जांच की गई। सूत्रों ने बताया कि जिले के अधिकांश शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किसी न किसी तरह से कांग्रेस के पार्षद कर रहे हैं। पिछले कुछ माह से आमजनों की शिकायत आ रही थी कि दुकानों में राशन नहीं मिल रहा है। मामले में भिलाई के वरिष्ठ भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा ने कलेक्टर से मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने भिलाई की दो दुकानों की जांच की। दुकानों का स्टॉक मिलान करने पर कई महीने का राशन बिना बांटे ही गायब मिला।

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कांग्रेसियों ने किया भव्य स्वागत

- **पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एकत्रित हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता**

धमतरी। बस्तर सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात प्रथम धमतरी आगमन पर भारी वर्षा के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह काम नहीं हुआ और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का आतिशबाजी, फूल-माला से भव्य स्वागत किया गया. स्वागत के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को हरेली पर्व की बधाई देते हुए नीम की पत्ती भेंट की. इस दौरान धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष लक्ष्मी ध्रुव, दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग राजकुमारी दीवान, महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी, पूर्व विधायक सिहावा अंबिका मरकाम, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष ओंकार साहू, जनपद अध्यक्ष मनीषा साहू, मदन मोहन खंडेलवाल गोपाल प्रसाद शर्मा, हरमिनदर छाबड़ा, अशरफ रोकडिया, विजय प्रकाश जैन, अरविंद दोषी, नजीर अली सिद्दीकी, अर्जुन लखवानी, डूंगर सिंह दामा, सूर्या राव पवार, सरीफ रोकड़िया,करण चन्द्राकर, शोभीराम नेताम, ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम साहू, आकाश गोलछा, ईश्वर देवांगन, मुकेश कोसरे, डीहुराम साहू, कैलाश प्रजापति, भूषण साहू, अखिलेश दुबे, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोनवानी, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई राजा देवांगन, जिला कोषाध्यक्ष सलीम रोकडिया, जिला महामंत्री आलोक जाधव, जिला पंचायत सभापति मीणा बंजारे, तारिणी चंद्राकर, गोविंद साहू, बृजेश जगताप, आनंद पवार, रजत जसूजा, योगेश शर्मा, राजेश ठाकुर, दीपक सोनकर, सोमेश मेश्राम, कमलेश सोनकर, आवैश हाशमी, अजय वर्मा, तनवीर कुरेशी, लखन पटेल, सलीम गौस, सरिता यादव, आशुतोष खरे, दिलीप बजाज, विक्रांत पवार, हितेश गंगवीर, तिलक सोनकर, अंबर चंद्राकर पवन यादव, प्रवीण नामदेव, उदित साहू, सूरज पासवान, चूकनेश्वर प्रशाद नागेंद्र, रेहान वीरानी, पंकज देवांगन, हेमलाल निर्मलकर, शास्त्री सोनवानी गणेश्वरी कॉमडे, अयूब खान, तारिख रज़ा कादरी, गुरु गोपाल गोस्वामी, गौतम वाधवानी, पवन तिवारी, अख्तर खान, जैनुद्दीन रिजवी, राकेश मौर्या, कीर्ति साह, गीतराम सिन्हा, तरुण रॉय, वसीम खिलची, नमन बंजारे, संजू साहू, तुसार जैस, नरेश छेदैहास, राजेंद्र ठाकुर, राजू कावड़े, कैलाश जैन, पेमन स्वर्णबेर, हरिख लाल समुंद, रवि निर्वाण, जीवराखन देवांगन, रामप्रसाद साहू, तारिख रज़ा कादरी, दिव्यांशु सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इंटर रिलिजन मैरिज में मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह

- **मुस्लिम समाज का बड़ा फैसला, समाज के लोगों ने निर्णय लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा**

गरियाबंद। लव जिहाद मामले को लेकर नवापारा मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला लिया है कि अब शहर में किसी भी इंटर रिलिजन मैरिज में मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हाल ही में गरियाबंद के छुरा गांव में हुए घटना की मुस्लिम समाज और इत्तेहाद कमेटी ने निंदा की और गरियाबंद जिला में भी यह फैसला लिया गया। इसको लेकर समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जिसके बाद इत्तेहाद कमेटी छत्तीसगढ़ मुस्लिम जमात व नवापारा मुस्लिम जमात प्रमुख मो. अल्तमश सिद्दीकी ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में छुरा में जो घटना हुई है। उससे हम सभी मुस्लिम समाज और इत्तेहाद कमेटी काफ़ी आहत है।

नवापारा मुस्लिम समाज व इत्तेहाद कमेटी ऐसे कृत्य और ऐसे कृत्य करने वालों का सामाजिक तौर पे बहिष्कार करेगी। अब कोई भी मन से अपने घर से भाग कर आये चाहे वह किसी भी जिले के निवासी हो या जिले के निवासी हो, चाहे वह दोनों प्रेमी प्रेमिका मुस्लिम समाज के ही क्यों ना या फिर प्रेमी मुस्लिम हो और प्रेमिका किसी और धर्म की। उनके प्रेम विवाह में मुस्लिम समाज इत्तेहाद कमेटी उनका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है, और जिले में ऐसे लोगों का कही भी कोई भी मौलाना निकाह नहीं पढ़ायेगा। इसके साथ ही कमेटी न कहा कि कोई भी गलत काम जैसे प्रेम विवाह, बलात्कर, चोरी-डकैती, लूटमार, किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाना और किसी भी प्रकार से समाज और नगर को बदनाम करता है। ऐसे व्यक्ति से हमारे समाज का कोई लेना देना नहीं हैँ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नीतीश विपक्षी एकता के सूत्रधार, नाराज नहीं हो सकते

पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश की नाराजगी की खबर को तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के सूत्रधार हैं और वह कभी नाराज नहीं हो सकते। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी राजद और जदयू के विलय का दुष्प्रचार फैलाया जाता है तो तभी राजद और जदयू के बीच टकराव की खबर फैलाई जाती है। गोदी मीडिया लगातार दुष्प्रचार करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं जो विपक्ष को एक साथ लाए हैं और जो व्यक्ति सभी को एक साथ लाता है वह कभी नाराज नहीं हो सकता। एनडीए की बैठक पर उन्होंने कहा कि मैं पांच साल तक एनडीए का हिस्सा था और आज तक पीएम मोदी ने कभी एनडीए के साथ बैठक नहीं बुलाई। अब उन्होंने बैठक क्यों बुलाई?... वे 2024 के चुनाव में हार जाएंगे।

बसपा अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और वह आगामी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का इरादा रखती है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में हम राज्य के क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव करीब हैं, हमारी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के वादों को खोखला बताया और कहा कि सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है। मायावती ने कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए समान विचारधारा वाली जातिवादी और पूंजीवादी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है।

भाजपा को राजग की तभी याद आई जब 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं: राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की याद तभी आई जब 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर 'इंडिया' समूह बनाने के लिए एकसाथ आ गईं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) की अगली बैठक मुंबई में होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों का यह गठबंधन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 'इंडिया' देश में 'तानाशाही' को हराएगा। राउत ने कहा, ''आपको राजग की याद तब आई है जब हम 26 (विपक्षी) पार्टियां देश के लिए 'इंडिया' बनकर पटना और बेंगलुरु में एक साथ आईं। इन बैठकों के बाद ही आपका कमल (भाजपा का पार्टी चिह्न) खिलना शुरू हुआ।' उन्होंने कहा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला 'इंडिया' करेगा।

एआईएमआईएम ने विपक्षी दलों की बैठक पर साधा निशाना

नईदिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने 2024 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबला करने के लिए बेंगलुरु में बैठक करने वाले विपक्षी दलों पर एआईएमआईएम को आमंत्रित नहीं करने पर हमला बोल। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली 26 पार्टियों के लिए वे राजनीतिक अछूत थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हैं। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती समेत ऐसे कई नेता हैं जो कभी बीजेपी के साथ थे। उन्होंने कहा कि हमने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को गाली देते देखा, लेकिन वह भी बेंगलुरु में बैठे हैं।

राजग लोकसभा की 330 सीट पर जीत हासिल करेगा

नईदिल्ली। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई के पलानीस्वामी ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) देश भर में 330 लोकसभा सट पर जीत हासिल करेगा। राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पलानीस्वामी से सवाल किया गया कि क्या महंगाई जैसे कारकों को देखते हुए कुल मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल करना संभव होगा, जिसके जवाब में अन्नाद्रमुक के नेता ने कहा कि देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसे पहलुओं के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश में कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था क्योंकि राजग चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा। पलानीस्वामी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में दुनियाभर में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

बेंगलुरु की बैठक पर बोले नीतीश कुमार- नाराजगी की बात मीडिया की उपज

मलमास मेले की वजह से जल्दी लौटा

पटना। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है। राजगीर मलमास मेले के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मीडिया में गलत बात चल रही है। बेंगलुरू में विपक्षी दलों की मीटिंग में हमारी सारी बात मान ली गई थी। हमलोगों को लौटना था इसलिए पहले ही चले आये। उन्होंने कहा कि मुझे राजगीर आना था इसलिए वहां से थोड़ी जल्दी में निकल आये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बेंगलुरु बैठक पूरी तरह सफल रही। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है।

राजगीर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग में हमलोगों ने सारी बात कह दिये हैं। इसलिए हम वहां से चले आये। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमको देर हो रहा था, तो हम चले आए। हमको राजगीर आना था, इसलिए हम चले आए। उन्होंने मीटिंग के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में शामिल नहीं पर नाराजगी की खबर को मीडिया की उपज बताया। कहा कि मीडिया पर उधर के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। मीडिया पर तो ऐसा ना नियंत्रण कर लिया है कि हमारा थोड़ा बहुत छाप देंगे। उधर से अंड बंड आएगा वही छापेंगे। अगले साल के चुनाव तक या इसी साल चुनाव करा देंगे, तब तक आपको(मीडिया) इधर-उधर करना होगा। लेकिन चुनाव के बाद आप लोग(मीडिया) स्वतंत्रता से काम करेगा।

हमलोग जिसको निकाल दिये, वो उसके साथ बैठक कर रहे हैं

संयोजक नहीं बनाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किये जा रहे तंज पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी बात पर क्या कहें, वो बैठक में थे। उनको रोज कुछ बोलना है। हमें कोई पद की इच्छा नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं। हम सबको एकजुट करने में लगे हैं। यह काम अच्छी तरह से हो रहा है। कल एनडीए की हुई बैठक पर नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए जब बना था अटल जी के समय तो बैठकें होती थी। हम कई बैठकों में शामिल हुए हैं। ये लोग एनडीए की बैठक कहां किया

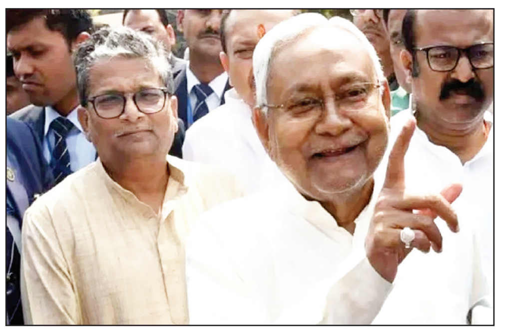

करते थे। अब हम लोग बैठक कर रहे हैं तो ये लोग भी बैठक बुला लिय। बताइये किसको किसको बैठक में बुला रहे हैं। हम लोग जिसको निकाल दिये, जो इधर का बात उधर कर रहा था, वो लोग उसे शामिल किये हैं। उनके साथ कौन-कौन है आप लोग ही देख लीजिए।

सब कुछ सबकी सहमति से हुआ

गठबंधन के नाम को लेकर पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। सबकुछ सबकी सहमति से हुआ है। हम लोगों ने अपनी बात रखी। हमारी सारी बातें मान ली गयी। जो नाम तय हुआ है वो सबकी सहमति से तय हुआ है। मीडिया रिपोर्टों में यह बात कही जा रही थी कि विपक्षी गठबंधन के नाम लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भारत से संबंधित नाम रखने का सुझाव दिया था, लेकिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' होगा। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया।

मुंबई की बैठक में तय होना है संयोजक

इससे पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि I.N.D.I.A. के संयोजक का ऐलान मुंबई के बैठक में होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार क्यों नाराज़ होंगे। ये सब मीडिया की उपज है। नीतीश कुमार खुद इस मुहिम शुरू करने वाले हैं तो फिर नाराज होने की बात कहां से आती है। उल्टा हमलोगों से भाजपा के लोग डरे हुए हैं इसलिए इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं। मोदी का एक पुराना वीडियो मैंने देखा जिसमे वो बोल रहे हैं वोट फ़ोर इंडिया तो अब भी वो इंडिया के लिए वोट माँगे और मैदान छोड़कर चले जाये। वहीं, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा को लेकर ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि अभी इस मामले को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब इन बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा सब चीज़ सबके सामने आ जाएगा।

कांग्रेस पीछे हटी तो टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद पर ठोंका दावा

कोलकाता। कांग्रेस पार्टी द्वारा संकेत दिए जाने के बाद कि उसे 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद प्रधान मंत्री की कुर्सी पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता शताब्दी रॉय ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी की प्राथमिकता व्यक्त की। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि उस मामले में हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी बनें। रॉय बंगाल के बीरभूम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले दिन में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का इरादा खुद के लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। उनकी टिप्पणी अगले आम चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी नेताओं की विशाल 26-दलीय बैठक को संबोधित करने के दौरान आई। खड़गे ने कहा कि राज्य स्तर पर पार्टियों के बीच मतभेद हो सकते हैं।, लेकिन जनता की खातिर उन्हें किनारे रखा जा सकता है। कांग्रेस नवगठित गठबंधन, जिसका नाम झ्.ह्.ष्.झ्. - भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है। अखिल भारतीय उपस्थिति वाली सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे की बातें गैर-कांग्रेसी दलों के नेताओं पर असर करती नजर आईं। गैर-कांग्रेसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह एक स्वागत भाषण है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को उदारता दिखाने और सभी को साथ लेने की जरूरत है।

केंद्र सरकार संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार

संसद का मानसून सत्र आज से

नई दिल्ली। मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को बताया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बीच विपक्षी दलों के नए गठबंधन 'इंडिया' की पहली बैठक आज यानी गुरुवार सुबह होगी।

सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि वह 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में नियमों के तहत स्वीकृत और सभापति द्वारा अनुमोदित हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सत्र के लिए कुल 32 विधायी मुद्दे हैं। सूत्रों की मानें तो जोशी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने को तैयार है।

बता दें, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से आरंभ होकर 11 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी 'इंडिया'

विपक्षी दलों के गठबंधन को आखिरकार मंगलवार को एक नाम मिल ही गया। अब नए गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' के नेता सरकार को संसद के मानसून सत्र में घेरने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसकी रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन 20 जुलाई को पहली बैठक करेगा। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को सुबह होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में होगी। गौरतलब है, विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के प्रयास के तहत मंगलवार को 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल

इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' नाम से नए गठबंधन की घोषणा की।

संसद में कांग्रेस इन मुद्दों पर चर्चा चाहती है

जयराम रमेश ने कहा कि हम संसद के आगामी सत्र में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा राज्यपालों और एलजी के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों पर हमला है, दिल्ली अध्यादेश इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरा मुद्दा मूल्य वृद्धि है... और निश्चित रूप से, अडानी घोटाले पर जेपीसी का मुद्दा। हम वन संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक और जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक मणिपुर हिंसा और रेल सुरक्षा पर वह चर्चा चाहती है। इसके अलावा संघीय ढांचे पर आक्रमण, जीएसटी को पीएमएल के तहत लाने पर चर्चा को लेकर भी वह गंभीर है। कांग्रेस की सूची में महंगाई, यूपीए सरकार की योजनाओं को कमजोर करने, महिला पहलवानों के उत्पीड़न भी शामिल है। इसके साथ ही अडानी मामले पर जेपीसी की मांग और अलग-अलग राज्यों के मुद्दे पर चर्चा कांग्रेस की मांग है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम सदन में कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। पहला मुद्दा मणिपुर है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मणिपुर के हालात पर चर्चा हो।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत ने बांग्लादेश को 108 रन से हराया

ढाका। भारत और बांग्लादेश की महिला टीम के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 108 रन से जीत लिया। ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 228 रन बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 120 रन पर सिमट गई और भारत ने मैच 108 रन से जीत लिया। इसके साथ ही तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली।

जेमिमा रोड्रिग्स ने मरुफा अख्तर को स्मृति मंधाना के हाथों कैच कराया और बांग्लादेश की पारी समाप्त की। मरुफा ने एक रन बनाया। इसके साथ ही भारत ने यह मैच 108 रन से जीत लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 228 रन बनाए। जेमिमा ने सबसे ज्यादा 86 रन का योगदान दिया। कप्तान हरमनप्रीत ने 52 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सुल्ताना और नाहिदा ने दो-दो विकेट लिए। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 120 रन ही बना सकी। फरगना हक ने 47 और ऋतु मोनी ने 27 रन का योगदान दिया। इन दोनों के अलावा सिर्फ मुर्शिदा खातून (12 रन) ही दहाई का आंकड़ा छू सकीं।

229 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने एक समय तीन विकेट पर 106 रन बना लिए थे और मैच में बनी हुई थी। हालांकि, इसके बाद 14 रन बनाने में टीम के सात विकेट गिर गए और भारत ने बड़ी हासिल की। भारत के लिए सबसे ज्यादा चार विकेट जेमिमा रोड्रिग्स ने लिए। देविका वैद्य को तीन विकेट मिले। इस मैच में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है और पिछले मैच में मिली शर्मनाक हार का बदला ले लिया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में तेजी जारी सेंसेक्स 67 हजार के पार

नईदिल्ली। स्टॉक मार्केट में बुधवार को तेजी का सिलसिला जारी रहा और विदेशों निवेशकों की जोरदार खरीदारी तथा वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव रुख के साथ बीएसई सेंसेक्स नए रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी के शेयर में तेजी से भी बाजार को समर्थन मिला। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी के साथ 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 302.30 अंक या 0.45 प्रतिशत की तेजी लेकर 67,097.44 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 376.24 अंक की उछाल लेकर 67,171.38 तक चला गया था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 83.90 अंक या 0.42 प्रतिशत चढ़कर 19,833.15 अंक के ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुआ। करोबार के दौरान निफ्टी 19,851.70 के नए रिकॉर्ड लेवल तक भी पहुंच गया था।

टाटा समूह ब्रिटेन में लगाएगा ईवी बैटरी प्लांट

नईदिल्ली। टाटा समूह ने 19 जुलाई को ब्रिटेन में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी प्लांट या गीगाफैक्टरी स्थापित करने पर बड़ी घोषणा की है। कंपनी इस गीगाफैक्टरी को स्थापित करने के लिए चार अरब पाउंड (5.2 बिलियन डॉलर) से अधिक का निवेश करेगी। टाटा समूह के इस निवेश से इससे सप्लाई चैन में हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। ब्रिटेन सरकार ने इस घोषणा का स्वागत किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे देश के मोटर वाहन उद्योग के लिए 'अविश्वसनीय रूप से गौरवपूर्ण' पल बताया है। उन्होंने कहा कि यह ब्रिटेन के कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तथा उसके श्रमिकों की ताकत को दर्शाता है। ब्रिटेन की लक्जरी कार विनिर्माता जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व 'टाटा मोटर्स' के पास है। यह 40 गीगावॉट घंटे के शुरुआती उत्पादन के वाले इस संयंत्र का प्रमुख ग्राहक रहेगी।

कोई इनकम नहीं है तो भी भरे आईटीआर

नईदिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। अधिकतर लोगों को लगता है कि जिनकी आय नहीं है या जिनकी आय टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आती उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप बेरोजगार हैं या आपकी आय कम है तो भी आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्योंकि इसके आपको कई फायदे मिलते हैं। जब आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना होता है और तब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो इसे जीरो रिटर्न या नील रिटर्न करते हैं। जब किसी टैक्सपेयर की इनकम एक फाइनेंशिलय ईयर में 2.50 लाख रुपये से कम होती है तो उनकी कोई टैक्स लाएबिलिटी नहीं होती। ऐसे लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वे लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं। अगर ऐसे लोग तब भी रिटर्न फाइल करते हैं, उसे नील आईटीआर या जीरो रिटर्न कहते हैं।

अगस्त की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में बदलाव नहीं करेगा रिजर्व बैंक : चेयरमैन

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखेगा। खारा ने बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, 'बैंक के रूप में हम नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक यथास्थिति को कायम रखेगा।' रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक आठ से 10 अगस्त 2023 को होनी है। गत आठ जून की मौद्रिक समीक्षा बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि, इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा था कि वह चाहता है कि महंगाई दर और नीचे आए।

एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को कायम रखा

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर कायम रखा है। एडीबी ने एशियन विकास परिदृश्य (एडीओ) पर बुधवार को जारी अपने ताजा जुलाई के आकलन में कहा है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग में सुधार की वजह से उसने वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सुस्ती से निर्यात घटने की स्थिति में यह अनुमान प्रभावित हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। एडीबी ने कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की वजह से चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को मामूली घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में उसने मुद्रास्फीति के पांच प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था।

एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है, ''मानसून और अन्य मौसमी कारक सामान्य रहने और भूराजनीतिक मोर्चे पर कोई और झटका नहीं लगने पर 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।'' एडीबी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग में सुधार की उम्मीद है। उपभोक्ता विश्वास, शहरी बेरोजगारी तथा मोटरबाइक की बिक्री के आंकड़ों से यही संकेत मिल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि निवेश वृद्धि मजबूत बनी हुई है। बैंक ऋण में बढ़ोतरी तथा घरों की मांग के आंकड़े यह दर्शाते हैं। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में कम बढ़ोतरी से भी समर्थन मिला है।

इसमें कहा गया है, ''हालांकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती से वस्तुओं का व्यापार

प्रभावित हुआ है, जो अंततः वृद्धि के लिए जोखिम बन सकता है।'' आपूर्ति पक्ष के बारे में इसमें कहा गया है कि इसे विनिर्माण से प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उत्पादन की लागत कम हुई है। मुद्रास्फीति के संबंध में एडीबी ने कहा कि खाद्य और कच्चे तेल की कीमतें घटने के बाद मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से नीचे आ गई है। खुदरा मुद्रास्फीति 2022 में ज्यादातर समय छह प्रतिशत से ऊपर रही थी। जून, 2023 में यह घटकर 4.81 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2023 में 4.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मजबूत घरेलू मांग से क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा ईंधन और खाने-पीने का सामान सस्ता होने से मुद्रास्फीति लगातार नीचे आएगी।

इसके महामारी-पूर्व के स्तर पर आने की उम्मीद है। ताजा आकलन में एडीबी ने एशिया-प्रशांत के लिए 2024 में वृद्धि दर के अनुमान को मामूली घटाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल में इसके 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। एडीबी ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था 2023 में पांच प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर के अनुमान में बदलाव नहीं किया गया है। एडीबी का अनुमान है कि 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रहेगी। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने कहा, ''एशिया-प्रशांत क्षेत्र लगातार महामारी से उबर रहे हैं।'' पार्क ने कहा, ''घरेलू मांग और सेवा गतिविधियां क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा कई अर्थव्यवस्थाओं को पर्यटन क्षेत्र में जोरदार पुनरुद्धार से लाभ हुआ है। हालांकि, औद्योगिक गतिविधियां और निर्यात कमजोर बना हुआ और वैश्विक वृद्धि और मांग का परिदृश्य कमजोर हुआ है।

कांग्रेस ने अपनी पार्टी के हितों का किया बलिदान

संतोष पाठक

पटना में विपक्षी दलों की बैठक में किए गए अपने वायदे को पूरा करते हुए बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक से पहले ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की एकता के लिए दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के हितों का बलिदान कर दिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस यानी राहुल गांधी के हितों का खयाल रखेंगे या नहीं? दरअसल, कांग्रेस के दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बलिदान का यह मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के नेता यह कतई नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नजर आए। भले ही वह मुद्दा दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश का ही क्यों ना हो। यहां तक कि पंजाब में पिछले चुनाव में हार कर सत्ता से बाहर होने के बावजूद कांग्रेस के स्थानीय नेता पंजाब में पुरजोर ताकत से आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के खिलाफ लड़ने का दावा कर रहे थे और इसलिए पंजाब कांग्रेस इकाई का भी यही कहना था कि मुद्दा चाहे कोई भी हो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए और कतई नहीं देना चाहिए। लेकिन अपने नेताओं की मांग और आम आदमी पार्टी के प्रति विरोध की भावना को दरकिनार करते हुए विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के हितों के विपरीत जाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करने यानी अरविंद केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगातार तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अधीर रंजन चौधरी भी लगातार यही कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ समझौता करने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन चूंकि मसला विपक्षी एकता का है इसलिए कांग्रेस ने अपने ही वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन नेता की बात को नकार दिया जिन्हें कांग्रेस ने लोकसभा में अपने संसदीय दल का नेता बना रखा है। अधीर रंजन चौधरी के कड़े रुख के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है और शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुद्दा राहुल गांधी द्वारा नहीं उठाए जाने पर भाजपा लगातार कांग्रेस आलाकमान को घेर रही है। यह फैसला कर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गेंद अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के पाले में डाल दी है। कांग्रेस आलाकमान इस बार भी 400 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए है, लेकिन विपक्षी एकता के नाम पर अगर उसे कुछ सीटें कुर्बान भी करनी पड़े तो कांग्रेस ऐसा करने को तैयार है।

स्वार्थ के चलते एकजुट हुए विपक्षी दल

ललित गर्ग

जब-जब विपक्षी दलों की एकता की बात जितनी तीव्रता से हुई, तब-तब वह अधिक बिखरी। विपक्षी दलों की पटना की बैठक से लेकर बैंगलोर बैठक के बीच काफी कुछ बदल चुका है। विपक्षी एकता से पहले ही बिखराव एवं टूटन के स्वर ज्यादा उभरे हैं। भले ही पटना की बैठक में शामिल 16-17 दलों की संख्या बेंगलुरु में 26 हो रही है। लेकिन अभी हाल तक जो नेता विपक्षी एकता की पैरवी कर रहे थे या फिर भाजपा से दूरी बनाए थे, उनमें से कुछ पाला बदल चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं जीतनराम मांझी और ओमप्रकाश राजभर। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा में विभाजन हो चुका है और विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार अपने दल में टूट की आशंका से ग्रस्त दिखने लगे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा भी अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विस्तार देने के लिए प्रयासरत है। मूल प्रश्न है कि विपक्षी एकता मोदी हटाओ के अलावा क्या कोई सकारात्मक एजेंडा लेकर सामने आ रही है, ऐसा लगता नहीं। समूचे राष्ट्र की जनता विपक्षी एकता की राजनीति को गंभीरता से देख रही है, बिना बुनियादी मुद्दों की चर्चा के ऐसी विपक्षी एकता कोई निर्णायक एवं प्रभावी होगी, इसमें संदेह है।

कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोध के बावजूद अब यदि एक मंच पर आने को सहमत हुए हैं तो यह स्पष्टत: सत्ता एवं स्वार्थ की राजनीति है। प्रश्न यह भी है कि क्या अब आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस पर अपने तीखे राजनीतिक हमले करने बंद कर देगी? इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि क्या बंगाल में कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के प्रति नरमी बरतने को तैयार होंगे? कांग्रेस को यह पहेली भी सुलझानी होगी कि क्या वह बंगाल में वाम दलों के साथ रहने और केरल में उनके विरोध में खड़े होने की अपनी विचित्र नीति पर चलती रहेगी? वास्तव में ये वे प्रश्न हैं, जो विपक्ष में व्याप्त अंतर्विरोध को ही दर्शाते हैं। हालांकि ये जो नए दल बेंगलुरु में विपक्षी एकता को बल देने के लिए पहुंच रहे हैं, वे मुख्यत: दक्षिण भारत में सीमित असर रखने वाले ही हैं, लेकिन विपक्ष के पास यह दावा करने का अवसर तो होगा ही कि अब उसके साथ कहीं अधिक दल हैं। इसके बाद भी यह कहना कठिन है कि अगले आम चुनाव तक वे सभी एकजुट रह पाएंगे, क्योंकि उनमें से अधिकांश दलों में इसे लेकर मंथन जारी है कि किस पाले में खड़े होने से लाभ होगा।

भारतीय राजनीति की नाटकीय परंपरा में विपक्ष की भूमिका अद्भुत एवं महत्वपूर्ण होते हुए लगातार निस्तेज हुई है, इससे लोकतंत्र भी कमजोर हुआ है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गयी है, वह राष्ट्रीय मंच पर छाया रहता है। लेकिन हमारा विपक्ष जरूरी जिम्मेदारियों से मुंह फेरते हुए मात्र राजसत्ता का भोग करने के लिये लालायित रहता है। जबकि विपक्ष को तीव्र आलोचना, आन्दोलन एवं विरोध की बजाय देश-निर्माण में भागीदारी निभानी चाहिए। विपक्ष निष्काम सेवा में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है- हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष दल कहां कर्म कर रहा है? राजनीतिक दलों ने 2024 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हटाने की ठान ली है। विपक्ष में होड़ मची है। क्योंकि एक दशक से विपक्षी नेताओं ने सत्ता-सुख नहीं भोगा है।

इक्कीसवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति आमूल-चूल बदल चुकी है। अब कोई भी सरकार जनाकांक्षाओं की अनदेखी नहीं कर सकती, फिर सत्ता की लालसा रखने वाला विपक्ष जनाकांक्षाओं की बजाय केवल सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा से कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। इस दौर में तटस्थता विपक्ष की सबसे बड़ी योग्यता होनी अपेक्षित है। साथ ही वह भी कि वह कितने लोगों को साथ लेकर चल सकता है। माई-बाप संस्कृति में रची-बसी देश की जनता नहीं जानती कि राष्ट्र प्रमुख होने का मतलब राष्ट्रीय मंच पर छाए रहना नहीं बल्कि देश के हित के लिए काम करना है। भगवद्गीता में कहा गया है कि सच्चा नेता वह है जो किसी मोह में पड़े बिना अपना काम करता रहे। उसके लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। लेकिन आज का विपक्ष तो सत्ता-मोह में उलझा है।

विपक्षी एकता तभी सार्थक एवं सफल होगी जब उनमें समझ और समझौते की मानसिकता हो। समझौते में शर्तें व दबाव होते हैं जबकि समझ नैसर्गिक होती है। इन्हीं दो स्थितियों में विपक्षी एकता संभव है। बैंगलोर में 26 परस्पर असमान विचारों वाले ग्रुपों के साथ न्यूनतम कार्यक्रमों के समझौते के आधार पर विपक्षी दल एकजुट होने के लिये जुट रहे हैं। हर स्तर पर एक समझौता होता है, नीतिगत और व्यवस्थागत। राजनीति तो चलती ही समझौतों के आधार पर है। जहां भी समझौता नहीं, वहां अशांति और असंतुलन/बिखराव हो जाते हैं। लेकिन जो एक सोचता है वैसा ही दूसरा सोचे, ऐसा राजनीति में कहां संभव है। समझौते के आधार पर कई बार अधिकारों को लेकर, विचारों को लेकर, नीति को लेकर फर्क आ जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। समझौता मौलिक नहीं होता, कई तानों-बानों से बनता है। इसमें मिश्रण भी है। माप-तौल भी है। ऊँचाई-निचाई भी है और प्राय: मजबूरी व दबाव भी सतह पर ही दिखाई देते रहते हैं। लगभग यही स्थिति विपक्षी एकता में बार-बार देखने को मिल रही है। जरूरत है समझौते से ज्यादा समझ को विकसित किया जाये। क्योंकि समझ प्राकृतिक है। समझौता मनुष्य निर्मित है। समझ निर्बाध जनपथ है। समझौता कंटीला मार्ग है, जहां प्रतिक्षण सजग रहना होता है। समझ स्वयं पैदा होती है। समझौता पैदा किया जाता है। पर जहां-कहीं समझ का वरदान प्राप्त नहीं है वहां समझौता ही एकमात्र विकल्प है। प्रजातंत्र में प्रदत्त अधिकारों की परिधि ने समझ की नैसर्गिकता को धुंधला दिया है। अत: समझौता ही हर जगह दिखाई देता है।

स्पष्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की भाजपा को चुनौती देने के लिए एकता की कवायद में जुटे विपक्ष के समक्ष अब बिखराव से बचना बड़ी चुनौती बन गई है। सत्ता केंद्रित राजनीति में नेताओं की निष्ठा और विश्वसनीयता संभवत: सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए अब दलबदल चौंकाता नहीं, बार-बार दलबदल देखने को मिल रहे हैं। व्यक्ति एवं परिवार केन्द्रित राजनीति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को धुंधलाया है। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए 1999 में शरद पवार द्वारा गठित राकांपा भी व्यक्ति और परिवार केंद्रित दल रही है। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए पिछले कुछ साल से आगे बढ़ाना शुरू किया, पर उससे पहले भतीजे अजीत पवार को भी परिवारवाद की सोच से ही आगे किया। उन्हीं अजीत पवार ने सुप्रिया को आगे बढ़ता देख पार्टी में ही दोफाड़ कर भाजपा से हाथ मिला लिया और उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही कभी बाल ठाकरे द्वारा बेटे उद्धव को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने पर भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत की थी। इस तरह की स्थितियां विपक्षी एकता की बड़ी बाधा है।

हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है या अपने दल को बढ़ते हुए देखना चाहता है, यह मानसिकता भी विपक्षी एकता के बढ़ते रथ को रोक सकती है। महाराष्ट्र में हुए बिखराव से और बिहार में महागठबंधन में अलगाव से विपक्षी एकता की कवायद का आत्मविश्वास निश्चय ही गड़बड़ाएगा। भाजपा ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया है कि जो अपना दल नहीं संभाल पा रहे, वे विपक्षी एकता और देश क्या संभालेंगे? जब सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ही अपने गठबंधनों को बढ़ाने एवं मजबूत करने में जुट गए हैं, तब 2024 की चुनावी जंग का नतीजा उस समय की राजनीतिक हवाओं एवं ताकत पर निर्भर करेगा कि उस समय किसके पक्ष में सकारात्मक हवाएं चल रही हैं। निश्चित ही अभी के राजनीतिक परिदृश्यों में भाजपा एवं मोदी के मजबूत पक्ष को देखते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अनेक नेता एवं दल जुड़ेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

ये सभी अनिष्टकारक तत्त्व आयु को क्षीण करने वाले कारण रूप हैं। इन सभी तत्त्वों को जानकर अपने कल्याण हेतु जप एवं ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। मन के द्वारा परम पिता परमात्मा का चिन्तन करते हुए तदनुरूप बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के अट्ठारह मर्मस्थलों में धारण किया जाना चाहिए। एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जाँघ का मध्य भाग, ऊरु का मध्य भाग, गुदा का मूलभाग, हृदय, उपस्थ, देह का मध्य भाग नाभि, कण्ठ, कोहनी, तालु-मूल, नासिका का मूल, आँखों का मण्डल, भौंहों का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, हाथों का मूल भाग हे द्विज! ये सभी स्थल इस पञ्च भौतिक शरीर के मर्म स्थान कहे गये हैं।

यमादि के द्वारा मन का धारण (एकाग्र) करना ही धारणा कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य संसाररूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। पैरों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्त्व का अंश कहा गया है। पीले रंग की चार कोण से युक्त पृथ्वी वज्र- लाञ्छिता (जटित) कही गई है। पाँच घटी (दो घण्टे तक वायु को ग्रहण करके पृथ्वी तत्त्व का चिन्तन करते रहना चाहिए। घुटनों से कमर तक का भाग जल का क्षेत्र कहा गया है।

इस जल का आकार अर्द्धचन्द्रमा की भाँति है। उसका रंग श्वेत शुभ्र है एवं चाँदी से लांछित (जटित) है। इसमें दस घटी अर्थात् (4 घंटे) तक श्वास रोककर जल तत्त्व का चिन्तन करना चाहिए। शरीर के कटि प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया है। उसका आकार अग्नि की लपटों की तरह तथा रंग सिंदूर के सदृश है। उसमें पन्द्रह घटी (छ: घण्टे) तक कुम्भक द्वारा प्राण तत्त्व को रोककर अग्नि तत्त्व का चिन्तन करना चाहिए। नाभि से नासिका तक का भाग वायु का स्थल कहा गया है, जिसका आकार वेदी के सदृश है। धूम्र की भाँति शक्तिशाली मरुत् का ध्यान बीस घड़ी अर्थात् (8 घंटे) तक कुम्भक द्वारा वायु को आरोपित करके करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरन्ध्र तक आकाश तत्त्व का स्थान कहा गया है, जिसकी आभा नीले रंग की कही गई है। प्रयत्नशील योगी साधक कुम्भक द्वारा प्राणवायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे। तदनन्तर पृथ्वी क्षेत्र वाले भाग में चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिन्तन करे। इस विधि से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाता है।

क्रमश: ..

विश्व शतरंज दिवस

शुभम यादव

दुनिया भर में न जाने कितने खेल खेले जाते हैं कुछ खेल शारीरिक होते हैं कुछ खेल मानसिक होते हैं कुछ खेल तकनीकी सहायता से खेले जाते हैं कुछ खेल भौतिक चीजों के समावेश से खेले जाते हैं इन्हीं खेलों में से एक सबसे रोचक और मानसिक चेतना को मजबूत करने वाला खेल है शतरंज का खेल। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसी दिन 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) की स्थापन हुई थी।

क्या है शतरंज के खेल का इतिहास

कैसे हुई होगी शतरंज के खेल की शुरुआत किसने लगाया होगा अपना दिमाग की शतरंज के प्यादे खेल के काम आ सकते हैं। कैसे शतरंज के प्यादों का निर्माण हुआ होगा। सबसे पहली और खास बात यह है कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में ही हुई थी और भारत से ही निकल कर यह खेल विश्व के जन जन के बीच मशहूर हुआ।

माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में होने के बाद यह पारसी देशों में प्रचलित हुआ, इसके बाद पूरे विश्व में पहुंचा। भारत में शतरंज खेलने की शुरुआत भी पांचवी-छठी शताब्दी के समय से मानी जाती है। जब इस खेल की शुरुआत भारत में हुई थी तब यह पहला खेल था जो दिमाग के इस्तेमाल से खेला जाता था। किंवदंतियों के अनुसार शतरंज का आविष्कार गुप्त काल के समय में हुआ।

वैसे तो महाभारत के प्रसंग में पांडव और कौरव पुत्रों के बीच चौसर का खेल खेला गया था। लेकिन गुप्त काल के राजाओं ने चौसर के खेल में बदलाव की चाह लिए शतरंज के खेल की शुरुआत की थी। शतरंज का आविष्कार कब हुआ था तब उसे इस नाम की बजाए चतुरंग खेल के नाम से जाना जाता था।

यूरोप और रूस जैसे देशों में शतरंज का खेल 9वीं शताब्दी तक पहुंच चुका था। लगातार शतरंज के खेल का प्रसार होता गया और आज लगभग सभी देशों में शतरंज के खेल को अपना लिया गया है।

शतरंज के खेल को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे-जैसे इस खेल का प्रसार हुआ वैसे वैसे ही इस खेल में कई तब्दीलियां आए कई नियम बदले गए तो कुछ देशों ने इस खेल के नाम को भी बदलने में रुचि दिखाई। पुर्तगाल में इस शतरंज के खेल को जादरेज का नाम दिया गया है। वहीं स्पेन में शतरंज को एजेडरेज कहा जाता है।

शतरंज के खेल में काले और सफेद खानों से मिलकर एक बोर्ड बना होता है, जिसमें कुल 64 खाने होते हैं। जिसमें 32 खाने सफेद रंग के और 32 खाने काले रंग के होते हैं। शतरंज के खेल में 2 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, दो हाथी, दो घोड़े, दो ऊंट और आठ सैनिक भी होते हैं।

शतरंज के खेल के नियम के अनुसार सफेद खाने का खिलाड़ी ही खेल की शुरुआत करता है। इस खेल में समय की कोई भी सीमा नहीं होती है। इंडिया चेस फाउंडेशन के द्वारा वर्तमान में शतरंज के खेल का नियंत्रण व प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है, जिसकी स्थापना सन् 1951 में की गई। वैश्विक स्तर पर शतरंज के खेल का नियंत्रण इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस खेल को खेलने में जो व्यक्ति मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है।

पाकिस्तान में चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार का संकट

बिक्रम उपाध्याय

पाकिस्तान के सामने आईएमएफ से कर्ज की अनिश्चितता खत्म हुई नहीं कि कयास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान में समय पर आम चुनाव होगा कि नहीं? मौजूदा नेशनल एसेम्बली का कार्यकाल 16 अगस्त को खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में रिवाज है कि चुनाव में जाने से पहले चुनी हुई सरकार घर चली जाती है और उसकी जगह एक केयर टेकर गवर्नमेन्ट आकर चुनाव कराती है। इसे निगरा हुकूमत कहा जाता है। अब इसी निगरा हुकूमत को लेकर नया संशय पैदा हुआ है कि क्या यह निगरा हुकूमत 60 से 90 दिन में चुनाव करा पायेगी? हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कह दिया है कि वो अगस्त में कार्यभार निगरा हुकूमत को सौंप देंगे। फिर भी निगरा हुकूमत को लेकर अविश्वास इसलिए है कि यह एक आम सहमति से चुनी जानी है, और इस आम सहमति में पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। समय पर चुनाव न होने को लेकर आशंका के पीछे सबसे बड़ा कारण है इमरान खान।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और फजल उर रहमान की जमात उलेमा ए इस्लाम के साथ पाकिस्तान की फौज भी इस बात पर एकमत हैं कि इमरान खान को अदालत से चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराकर या उन्हें जेल भेजकर ही चुनाव की घोषणा की जाए। अब इसमें कितना समय लगता है यह अदालत के कामकाज पर निर्भर करता है। यह लगातार देखा जा रहा है कि कई अदालतें और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर मेहरबान हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बांडियाल का तो इमरान को खास संरक्षण प्राप्त है। इसलिए यदि इमरान के खिलाफ कोर्ट से फैसला आने में देरी होती है तो चुनाव भी देरी से हो सकते हैं।

पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्मेंट को लेकर गहमागहमी पहले से ही शुरू है। जून के आखिरी सप्ताह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (पीएमएल-एन) के प्रमुख नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के शीर्ष नेता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने दुबई में एक गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में निगरा हुकूमत के स्वरूप और अगले चुनाव की चुनौतियों पर व्यापक मंथन हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार उस बैठक में कम से कम अगले साल मार्च तक चुनाव टालने के विकल्प पर भी विचार किया गया और तय किया गया कि एक ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप दी जाए, जो दोनों दलों के हितों का ध्यान भी रखे और किसी न किसी बहाने चुनाव को टालता रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कोई वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है जिस पर राजनीतिक लाभ हानि का कोई असर ना हो। पाकिस्तान में इस तरह का प्रयोग चल रहा है और अभी तक सफल भी रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) की एसेम्बली पिछले जून में ही भंग कर दी गई थीं और दोनों जगह कार्यवाहक व्यवस्थाएं लागू कर दी गई थी। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार एसेम्बली भंग होने के 90 दिनों के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां अभी तक चुनाव नहीं हुए। दोनों जगह के गवर्नर मनमाने ढंग से सरकार चला रहे हैं।

पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर अनिश्चितता का एक और कारण हैं तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। उन पर आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा हुआ है और यह प्रतिबंध तभी हट सकता है, जब तीन चौथाई बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी बेंच सुनवाई कर अपने पहले के फैसले को बदल दे। दो तिहाई बहुमत की संभावना फिलहाल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले की सुनवाई का कोई संकेत नहीं दिया है। पीएमएल एन का मानना है कि मौजूदा चीफ जस्टिस बांदियाल के रहते हुए नवाज शरीफ को राहत नहीं मिल सकती। इसलिए जस्टिस उमर अता बांदियाल के जाने तक इंतजार करना पड़ सकता है। जस्टिस बांदियाल 17 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जस्टिस फैज ईसा चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। जस्टिस ईसा पर पीएमएल एन को पूरा विश्वास है, क्योंकि वे इमरान खान के सताए हुए हैं और जस्टिस ईसा ने ही खान पर भ्रष्टाचार का केस दायर किया है। पीएमएल एन अगला आम चुनाव नवाज शरीफ के नाम पर लड़ना चाहती है इसलिए बहुत हद तक संभव है कि अदालत से उन्हें राहत दिलाए बिना नवाज की पार्टी चुनाव के लिए ना जाए। हालांकि पीपीपी और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ के सामने कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ चुनाव के लिए तैयार हैं, बशर्ते सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाएं और शरीफ को वापस लौटने और चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाए। नवाज शरीफ यह साबित करने के लिए सत्ता में लौटना चाहते हैं कि 2017 में उनका निष्कासन गलत और अवैध था। पीएमएल एन ने सरकार छोड़ने से पहले यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान को आर्थिक और सियासी तौर पर वही स्थिरता दे सकती है। खासकर आई एम एफ से लोन लेने के मामले में सारा श्रेय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। महीनों से अटके पड़े आईएमएफ समझौते को पूरा करने में उनके योगदान का खूब प्रचार किया जा रहा है। शाहबाज शरीफ ने ही आईएमएफ प्रबंध निदेशक जार्जीविया से पेरिस में मिलकर व्यक्तिगत तौर पर यह आश्वस्त किया कि उनका देश आईएमएफ की सभी शर्तों को मानेगा। उसके बाद ही आईएमएफ ने 3 अरब डॉलर की स्टैंड बाई व्यवस्था को मंजूरी दी।

14 जुलाई को आईएमएफ प्रमुख ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ को फोन कर यह दुहराया कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाली केयरटेकर गवर्मेंट भी आईएमएफ प्रोग्राम को लागू करेगी। आईएमएफ ने जिस दिन 1.2 अरब डॉलर की किश्त दी उसी दिन पाकिस्तान में पौने पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल में बढ़ोतरी की दी गई। फिल्हाल शरीफ गवर्नमेंट को यह श्रेय मिल रहा है कि इसने मुल्क को डिफाल्ट होने से बचा लिया। इधर इमरान खान अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 9 मई के हादसे के बाद पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के छोड़ जाने के बावजूद वह दावा कर रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे वही जीतेंगे। इमरान खान तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उनके जेल जाने या तहरीक ए इंसाफ पर पाबंदी लगाने की सूरत में वह नई पार्टी बनाकर चुनाव में जाएंगे और जीत भी जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के अधिकतर मीडिया हाउस और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि पीटीआई चेयरमैन का भविष्य अंधेरे में है। उन पर इतने मुकदमें लाद दिए गए हैं कि उनका सभी से बचना मुश्किल है। देर सबेर अदालत द्वारा दोषी ठहरा ही दिए जाएंगे। फिर इमरान खान और पीटीआई को लेकर शरीफ और जरदारी दोनों एक ही निर्णय पर हैं और वे सुनिश्चित करना चाहंगे कि खान को अयोग्य करार दिया जाए और इसके लिए वे खुद के उदाहरणों का हवाला भी दे रहे हैं।

बापू की दिनचर्या

डायरी-लेखन और माला-जप (भाग-2)

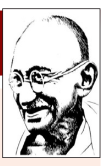

गतांक से आगे...

सर्वविध सफलता के लिए यह अमोघ अस्त्र है। डायरी को न इतिहास कहना संभव है, न आत्मकथा, लेकिन इन दोनों का जितना प्रभावी संयोग डायरी में होता है, उतना किसी अन्य विधा में नहीं डायरी की प्रत्येक घटना या उसके हर प्रसंग से उसके लेखक का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार जुड़ा रहता है कि जहाँ उससे इतिहास के कई पहलू स्पष्ट होते हैं, वहीं उसकी जीवनयात्रा का चित्र भी बनता रहता है। यह चित्र यदि निष्ठापूर्वक प्रस्तुत किया गया हो तो आत्मकथा से कम सरस या निमग्नकारी नहीं होता। साथ ही, यदि डायरी लेखक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो तो डायरी रूपी चित्रों से वह सुशोभित हो सकता है। डायरी स्वयं से स्वयं की बातचीत है। दर्पण में हम तन देखते हैं, डायरी में मन। इस कारण उसमें समाविष्ट होनेवाला निजत्व या आत्मीयता पत्र के निजत्व या आत्मीयता से आगे की चीज है। डायरी लेखन का कार्य बापू के शब्दों में सत्य की आराधना के समान है और सत्य का उनसे बड़ा आराधक इस युग में या इस शताब्दी में दूसरा कौन हो सका? शयन से पूर्व, अंतिम कार्य के रूप में बापू अपने राम को अवश्य स्मरण करते। उनके बिस्तर पर तकिए के पास उनकी माला रहती। जब वे अफ्रीका में थे, तब भी राम-नाम की माला जपा करते। अंत तक उनका यह क्रम चलता रहा, किंतु उनके जीवनकाल में इस तथ्य की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। उनका जीवन पुस्तक के खुले पृष्ठों के समान था। वे रात- बिरात चुपके-चुपके राम-नाम जपा करते। उनका जप आत्मसंतोष के लिए होता और वे यह नहीं चाहते थे कि कोई दिखावे के लिए उनका अंधानुकरण करे। एकाध बार खास समय और संख्या के लिए वचनबद्ध होने का प्रसंग आने पर बापू ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, क्योंकि वे रात- दिन जो-कुछ करते, सब राम-नाम के लिए करते। इसका मतलब यह नहीं कि वे निश्चित संख्या और समय के विरुद्ध थे, बल्कि ऐसे आयोजनों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते। उनकी मान्यता थी कि जप करनेवालों में यदि कुछ लोग भी हृदय से जप करनेवाले निकले तो उनका तथा देश का बहुत कल्याण होगा। 'कल्याण-संपादक भाईजी हनुमानप्रसाद पोद्दार से एक भेंट- वार्त्ता में बापू ने उपर्युक्त विचार प्रकट किए थे। रामनाथ सुमनजी न एक बार कहा था और बिलकुल सही कहा था। कि बापू परम भागवत थे।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल को प्रमुख लोकायुक्त शर्मा ने सौपा वार्षिक रिपोर्ट

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस (से.नि.) श्री टी. पी. शर्मा ने राज्यपाल से भेंट कर लोक आयोग का वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह लोक आयोग का 21वां प्रतिवेदन है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, लोक आयोग के सचिव श्री अनुराग पाण्डेय भी उपस्थित थे।

राज्यपाल से रावतपुरा सरकार विवि के कुलपति ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस. के. सिंह ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह आयोजन के संबंध में चर्चा की। उनके साथ कुलसचिव डॉ. सौरभ शर्मा भी उपस्थित थे।

आमरण अनशन करेंगे हजारों संविदा कर्मी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी अब अपने आंदोलन को बड़ा रूप देने जा रहे हैं। बुधवार से इन संविदा कर्मचारियों ने आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर पिछले 2 सप्ताह से संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों के आंदोलन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं।

मंडल संयोजक पद के लिए ऑनलाईन आवेदन 7 अगस्त तक

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत मंडल संयोजक पद की भर्ती परिसीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधीनस्थ सेवा (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) भर्ती नियम 2011 एवं संशोधित भर्ती नियम 2018 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मंडल संयोजक के पदोन्नति कोटा में रिक्त पदों पर सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-03 एवं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी-द के आवेदक परिसीमित विभागीय परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाईन आवेदन/डाक कुरियर से कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम भर्ती नियम में दिए प्रावधान अनुसार होगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करने वाले सात नाबालिग पकड़े गए

भाटापारा। बिलासपुर-नागरपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर क्षतिग्रस्त करने के आरोप में आरपीएफ ने सात नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ट्रेन पर पत्थर इसलिए फेंके क्योंकि उन्होंने सुना था कि पत्थर लगते ही ट्रेन से सायरन की आवाज आती है। इसे परखने के लिए उन्होंने गुलेल से ट्रेन पर पत्थर मारे थे। जानकारी के मुताबिक, गाड़ी संख्या 20826 नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में तिल्दा स्टेशन के बाद पत्थर फेंकने की घटना से वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर सी 3 के 50,51, 52 सीट नंबर के बगल वाले कांच की खिड़की क्षतिग्रस्त हुई थी। मुखबिर की मदद से आरपीएफ आरोपियों तक पहुंची। आरोपियों ने खुलासा किया कि वह 14 जुलाई को गुलेल लेकर कबूतर मारने के लिए घूम रहे थे कि इसी दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। उन्होंने सुना हुआ था कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारने से सायरन बजता है। तो उन्होंने गुलेल से पत्थरबाजी की। आरोपियों का बयान दर्ज करने के बाद आरपीएफ ने सभी को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया।

मुख्यमंत्री से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में विधानसभा के शैक्षणिक परिभ्रमण में आए दुर्ग जिले के देवादा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री बघेल से विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्हें विधानसभा की कार्यवाही प्रत्यक्ष देखने को मिली। बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने देवादा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

आयकर विभाग ने आधा दर्जन से अधिक राइस मिलरों के यहां मारा छापा

रायपुर। राज्य में कल जहां स्टील और पॉवर कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी थी वहीं आज आधा दर्जन से अधिक राइस मिलरों के यहां छापेमारी की कारवाई की है। जिनमें बिलासपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर सिंह सलूजा भी शामिल है जिनकी दो राइस मिल हैं। मंगलवार की देर शाम आयकर विभाग की टीम धमतरी के अजय बरडिया, आशीष लुकंड़, दुर्ग में कैलाश रुगंटा के यहां दबिश दी है। इसके अलावा महासमुंद के राइस मिलर पारस चोपड़ा और रायपुर के खरोरा में स्थित बालाजी राइस मिल में भी जांच-पड़ताल चल रही है। करीब एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों में जांच-पड़ताल जारी है। आयकर टीम ने मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी के अमलीडीह स्थित खुशी वाटिका में भी दबिश दी है।

संभागायुक्त डॉ अलंग ने विकास कार्यों का लिया जायजा

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त डॉ संजय अलंग ने बुधवार को बलौदा बाजार-भाटपारा जिले के सिमगा, भाटापारा तथा बलौदाबाजार विकासखण्ड में विभिन्न विकासमूलक कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों तथा विभिन्न योजना के हितग्राहियों से सीधा संवाद करते हुए योजना अंतर्गत मिलने वाले लाभ के बारे में पूछताछ की तथा जहां सुधार की जरूरत थी वहां अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री चंदन कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, उपायुक्त श्रीमती सरिता तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कमिश्नर डॉ अलंग ने सर्वप्रथम सिमगा विकासखण्ड के ग्राम पंचयात कामता पहुंचकर गौठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों, अमृत सरोवर तथा जल जीवन मिशन के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने यहां अमृत सरोवर तालाब के मेड पर पौधरोपण कर जिला स्तरीय वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में करीब 4 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। कमिश्नर ने गौठान का निरीक्षण कर गोबर खरीदी, गौधन न्याय योजना अंतर्गत हुए आय-व्यय एवं गौठान में चल रहे आजिविका गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने आजिविका गतिविधी जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन एवं बकरी पालन इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया । इसके साथ ही गौठान में हो रहे लेमन ग्रास खेती को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त क्षेत्र का चिन्हांकन करते हुये लेमन ग्रास आइल एक्सट्रेशन यूनिट लगाने हेतु निर्देशित किया।

इसके पश्चात कमिश्नर डॉ अलंग ने भाटापारा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत गुडेलिया गोठान में संचालित गतिविधियों का अवलोकन करते हुए स्व सहायता समूह की महिलाओं से गोठान में संचालित गतिविधियों से जुड़कर जीवन मे आए सकारात्मक बदलाव के सम्बंध में जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि गोठान व रीपा से जुड़कर उनकी आर्थिक स्थित में काफी सुधार आया है। परिवार के सदस्य भी उनकी सहायता करते है। गुड़ेलिया गोठान में रीपा अंतर्गत पावर ब्लॉक निर्माण, फ्लाई ऐश निर्माण, खिला निर्माण, चौन लिंक फेंसिंग निर्माण, मसाला उत्पादन इकाई स्थापित किया गया है।

कमिश्नर डॉ अलंग सहित अधिकारियों ने गोठान परिसर में करंज के पौधे रोपे। इसके पश्चात कमिश्नर ने पूर्व माध्यमिक शाला गुड़ेलिया तथा हमर क्लिनिक व जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हितग्राही रूपा यादव के घर मे लगे नल जल का अवलोकन किया और हितग्राही से नल जल से मिल रही सुविधा की जानकारी ली। उन्होंने ग्राम अर्जुनी में ओम स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा की जा रही मुर्गी पालन व बाड़ी विकास कार्य का भी अवलोकन किया और अब तक अर्जित आय की जानकारी लेते हुए बेहतर संचालन करने पर समूह की महिलाओं की सराहना की।

सी-मार्ट का अवलोकन

कमिश्नर डॉ अलंग ने बलौदाबाजार में संचालित सी मार्ट का अवलोकन किया। यहां समूह की महिलाओं द्वारा गोठान में निर्मित काष्ठ शिल्प अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आकर्षक उत्पाद को बिक्री के लिए रखा गया था जिसे अवलोकन करते हुए उन्होंने समूह की महिलाओं की तारीफ की। इस दौरान समूह की महिलाओं ने काष्ठकला की सुंदर उदाहरण पेश करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भेंट की। कमिश्नर ने सी- मार्ट के बेहतर संचालन हेतु अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए।

खोरसी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण का निरीक्षण

बलौदाबाजार विकासखण्ड के खोरसी-खपरी-खैन्दा-रसेड़ा मार्ग के खोरसी नाला पर करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे उच्च स्तरीय पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निर्माण समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुल का निर्माण जनवरी 2024 तक करीब 14 माह में पूर्ण किया जाना है।

फर्जी जाति की समीक्षा करेंगे अमिताभ जैन

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी करने वालों के खिलाफ की गई अब तक की कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। एससी और एसटी विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने 16 विभागों को पत्र जारी किया है। समीक्षा बैठक 20 जुलाई को होगी। सभी अफसरों को शामिल होने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें फर्जी दस्तावेज के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी साथ में लाने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रायपुर के विधान सभा क्षेत्र में हुए निर्वस्त्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस मामले में यह कदम उठाया है।

नग्न प्रदर्शन को लेकर हंगामा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही रायपुर में विधानसभा रोड पर एससी-एसटी युवाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने विधानसभा को घेरने की भी कोशिश की थी। आमासिवनी के पास फर्जी आरक्षण प्रमाणपत्रों का आरोप लगाते हुए करीब 12 युवाओं ने पूरी तरह नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन किया। युवाओं ने फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वालों का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधियों से मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में 29 प्रदर्शनकारी युवाओं को गिरफ्तार किया है। सभी पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। विधानसभा में बुधवार को राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने निर्वस्त्र प्रदर्शन करने के मुद्दे पर कांग्रेस नीत सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की।

विपक्ष के सदस्यों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की।सदन में प्रश्नकाल के बाद इस विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और बृजमोहन अग्रवाल तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्यों इंदु बंजारे और केशव चंद्रा ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के 'निर्वस्त्र' होकर प्रदर्शन करने से देश-विदेश में राज्य की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए राज्य सरकार ने उन प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। विपक्ष के सदस्यों ने काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

इस मामले को लेकर भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि यह घटना छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। इस पर कांग्रेस मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि यह आप लोगों के द्वारा किए गए पाप हैं। भाजपा शासन में फर्जी नियुक्ति की, जिसके बाद 15 साल तक भाजपा ने फर्जी काम किए। मंत्री के इस बयान के बाद सदन में मौजूद बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई करना चाहिए, न कि प्रदर्शनकारी युवाओं पर। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार युवाओं को निर्वस्त्र प्रदर्शन करने पर मजबूर करे, इससे हम सभी शर्मसार हुए हैं। इस मामले पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस मामले पर हाई पावर कमिटी से जांच कराई जाए।

जैजैपुर विधानसभा से बसपा विधायक केशव चंद्रा ने कहा कि जब कोई साधु नग्न होकर आता है तो उसकी पूजा की जाती है, लेकिन एक युवा अपने हक की बात करने के लिए आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह संवेदनशील मामला है। इस मामले को राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति इससे संकोची होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़ा, इस मामले को लेकर चीफ सेक्रेटरी और विभाग के अधिकारियों की हाई पावर कमिटी बनाई जाए। इस मामले पर पूर्ण रूप से जांच की जाए। इसके बाद सदन में मामले को लेकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा।विपक्ष के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन में हंगामा किया जिसके कारण कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। वहीं हंगामे के दौरान गर्भगृह में आने को लेकर भाजपा विधायकों को कुछ समय के लिए निलंबित किया गया। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने विपक्ष का विरोध करते हुए दावा किया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान फर्जी जाति प्रमाणपत्र वाले लोगों को नौकरी दी गई। सदन में हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी।

डॉ खूबचंद बघेल का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज डॉ खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के फूल चौक स्थित डॉ खूबचंद बघेल व्यवसायिक परिसर नवीन मार्केट में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परिसर में स्थापित डॉ खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि डॉ खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के पहले स्वप्नदृष्टा थे। छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉ खूबचंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे एक कुशल संगठक, चिकित्सक, किसानों के हितैषी, सहकारिता आंदोलन के अग्रणी, लेखक व अच्छे कलाकार भी थे। डॉ खूबचंद बघेल ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उनकी मां और पत्नी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीं।देश की आजादी का समय हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण का काल था। उस समय यह प्रश्न था कि एक नए भारत में छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे पर कैसे उभारा जाए ।

20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी से राज्य की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आयेगा: बैज

■ मंत्रीमंडलीय उपसमिति के निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करने के मंत्री मंडलीय उपसमिति का निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे समृद्ध किसान होगा। इस वर्ष कांग्रेस की सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसान प्रति एकड़ लगभग 60,000 रू. का धान बेचेगा, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साबित कर दिया कि सही मायने में छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। एक तरफ देश भर में खेती किसानी घाटे का सौदा हो गयी है। छत्तीसगढ़ में खेती करके किसान समृद्ध और खुशहाल हो रहे है।

बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्या को गहराई से जानते और समझते हैं। इसलिए वे किसानों के भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजना संचालित कर रहे है। भूपेश सरकार में 20 लाख किसानो की 11 हजार करोड़ का कृषि ऋण माफ हुआ है, 350 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ है, 5 लाख से अधिक स्थाई पंप कनेक्शन दिए गए हैं और किसानों के बेहतरी के लिए राज्य की सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। बीते 4 वर्ष में लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में राज्य सरकार ने डाले है। साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर किसानों को और अधिक लाभ पहुँचा रहे है। 20 क्विन्टल प्रति एकड़ धान खरीदी होने से अब सभी किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9000 रू. प्रति एकड़ किसानों को मिल रहा है।उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान होते है। इस हेतु प्रदेश सरकार किसानों के हितों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। जनहितकारी योजनाओं से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाने से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ होगा। किसानों के आय में वृद्धि होगी, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा। बैज ने कहा कि भाजपा की कथनी, करनी का अंतर हमेशा से अलग रही। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते भाजपा ने वायदा किया कि धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 5 साल तक 300 रूपये बोनस देंगे, 5 साल नही दिया। धान का एक-एक दाना खरीदेंगे, नहीं खरीदा। 10 क्विंटल खरीद रहे थे कांग्रेस के विरोध के बाद बढ़ाया। 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने वायदा किया था स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे लागत मूल्य का डेढ़ गूना समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे। 2022 बीत गया किसानों की आय बढने के बजाये घट गयी, अब कांग्रेस की द्वारा की जा रही धान खरीदी पर भी भाजपाई श्रेय लेने की घटिया राजनीति पर उतर आये है।

मुख्यमंत्री बघेल 23 को करेंगे युवाओं से करेंगे विकास के मुद्दे पर चर्चा

■ तैयारियों पर कलेक्टर भुरे ने की अधिकारियों संग बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रविवार 23 जुलाई को संभवतः रायपुर संभाग के युवाओं से भेंट-मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इण्डोर स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान संभाग के पांचो जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, मितान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहें प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से बातचीत करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आज कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कार्यक्रम के लिए कानून व्यवस्था, आयोजन संबंधी इंतजामों आदि की समय पर तैयारियों के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की युवाओं से भेंट-मुलाकात कार्यक्रम को पूर्व में आयोजित प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान का विस्तार माना जा रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शासकीय योजनाओं के लिए लोगों का फीडबैक भी जाना था। अब सभी संभाग मुख्यालयों में समय-समय पर होने वाले युवाओं से भेंट-मुलाकात के इस कार्यक्रम में श्री बघेल छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ गढने के लिए युवाओं की सोच और सुझाव भी लेंगे।

बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समीक्षा

■ बुनियादी स्तर पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को चिन्हित करने पर जोर

रायपुर।बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बुनियादी स्तर हेतु तैयार राज्य की पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया। लाइब्रेरी के अधिकतम उपयोग पर चर्चा की गई। ऐसे क्षेत्रों में जहां बहु भाषा का उपयोग की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने सभी बच्चों को सिखाने की रणनीति पर आयोजित बैठक में कहा कि राज्य के बच्चों को हम बेहतर कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों के उपलब्धि स्तर को और कैसे बढ़ा सकते हैं उनके अकादमिक प्रक्रिया में क्या-क्या परिवर्तन किया जा सकता है तथा किस तरह की पैडागॉजी को शामिल किया जा सकता है। इन मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे। उपस्थित प्रतिभागियों ने सुझाव देते हुए बताया कि, अकादमी परिप्रेक्ष्य के लिए क्लास रूम की प्लानिंग की आवश्यकता है। शिक्षकों के पास डे-टु-डे की प्लान बनाने की आवश्यकता है। वर्क बुक पर डे-टु-डे कैसे कार्य किया जाए, इस मुद्दे पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने यह भी सुझाव दिया कि टीचर गाइड का क्रियान्वयन किया जाए। कक्षा कक्ष के भीतर ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो नहीं सीख पा रहे हैं। अतः फॉर्मेटिव एसेसमेंट का क्रियान्वयन उचित ढ़ंग से किया जाए। अधिकांश शिक्षक पुरानी पद्धति के साथ शिक्षण कराते हैं। बैठक में बताया गया कि सुग्घर पढ़वईया कार्यक्रम में अधिकांश विद्यालय ने चुनौती ली है। ऐसे विद्यालय जिन्होंने अभी तक चुनौती नहीं ली है उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो तथा अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों को स्वयं का आकलन कर थर्ड पार्टी आकलन हेतु अनुरोध किए जाने हेतु तैयार किया जावेगा। इसके लिए उन्हें आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।बैठक में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में राज्य में सहयोग कर रहे एनजीओ आह्वान ट्रस्ट, रूम-टू-रीड, एलएलएफ, एपीएफ, संपर्क फाउंडेशन, एवं स्टोरी विवर, प्रथम एवं परिषद के अकादमिक सदस्य उपस्थित थे।

वादे पूरा करने के बजाय झुनझुना पकड़ा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल: डॉ. रमन सिंह

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल के फैसलों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने पिछले पौने 5 साल केवल घोटाले और प्रदेशवासियों का शोषण करने में बीता दिए और अब चुनाव पास देखकर भी अपने वादों को पूरा करने के बजाय जनता को झुनझुना पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल से 5 लाख कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं, महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया पर उनके एरियर्स का भुगतान कब होगा? साथ ही उन्होंने नियमितीकरण के वादे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि पौने 5 साल बाद संविदाकर्मियों को 27त्न का झुनझुना पकड़ा दिया है, नियमितिकरण कब होगा?, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही थी उसका क्या हुआ?

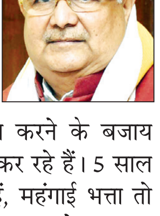

जहरीली शराब से 3 लोगों की हुई मौत, हर जिले में बिक रही अवैध शराब

विधानसभा में शराब पर सियासत

रायपुर। विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग छिड़ गई है. दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों का ठिकारा मढ़ रहे हैं. इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई है. सरकार का कहना है कि, पूरे प्रदेश में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है.

नारायण चंदेल ने कहा, जांजगीर चांपा क्षेत्र के मृतक 3 में से 1 जवान भी शामिल है. गांव के किराना दुकान से उन्होंने शराब खरीदा था. उस क्षेत्र में कोई अधिकारिक शराब दुकान नहीं है. उस दुकान वाले के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग गांव वाले करते रहे हैं. यह सिर्फ तीन लोगों की मौत का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में अवैध शराब बिक रही है. यह शासन के संरक्षण में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है. आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी को इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे. न सभी के मिलीभगत का यह खेल है. जहां 3 लोगों की मौत हुई, वहां शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया. हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं.वहीं युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, यह किसी भी सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक है. ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी ? उन्होंने पहले ही प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि, यदि फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच और कार्रवाई नहीं होगी तो नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे. उसके बाद भी शासन-प्रशासन चुप रहा. सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा ? इसके लिए दोषी कौन है ? इस पूरे घटना की जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है.

शराब पीने से नहीं हुई थी युवकों की मौत : लखमा

इस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई है, बल्कि जहर पीने से तीन युवकों की मौत हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में देशी-विदेशी शराब दुकानों की जानकारी चाहते हुए आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत हुई है। चंदेल ने नाम भी गिनाए । अवैध शराब की बिक्री हो रही है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। लखमा ने कहा कि शराब पीने से किसी की मौत नहीं हुई है। मौत दवा पीने से हुई है। उन्होंने किसी भी मौत से इंकार किया है। विपक्ष ने इस पूरे मामले की सदन की कमेटी से जांच की मांग की। इस पूरे मामले पर विपक्ष के सवालों से आबकारी मंत्री घिर गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस प्रकरण में जांच को अधूरा करार दिया है। उन्होंने विभागीय मंत्री को कल फिर से जवाब देने के लिए कहा है।

अनुपूरक बजटः 2000 करोड़ रूपए की घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान शासकीय कर्मियों के हित में बड़ी घोषणाएं की।

- लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि, इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

- सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।
- शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगारी भत्ते पर मंत्री पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा ने किया वॉकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी भत्ते का मामला उठाया, जिस पर विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने पूछा कि 22 हजार लोगों को रोजगार देने का विज्ञापन दिया तो 33 हजार लोगों की भर्ती कैसे हो गई। विभागीय मंत्री ने माना कि 22 हजार विज्ञापन में 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है इसके लिए अलग-अलग विभागों में व्यवस्था की गई।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने लगाया आरोप लगाया कि बेरोजगारों को भत्ता देने के नियम रोज बदले जा रहे हैं। सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के होर्डिंग लगा रही है, लेकिन कितने बेरोजगार पंजीकृत है, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। विभागीय मंत्री उमेश पटेल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी पंजीयन के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है। ये हास्यास्पद है। चर्चा के दौरान मंत्री उमेश पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे अजय चंद्राकर अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, अभी न जाएं, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा।

मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 ने बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराया है। 20 जून 2023 की स्थिति में 1,14,764 पात्र एवं 33559 अपात्र हुए हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना किसी को नौकरी दिए 33 हजार 659 अपात्र हो गए। शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा के सदस्य इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आए और जमकर हंगामा किया इसके बाद सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया।

इस सरकार को सिंडिकेट चला रहे हैंः अजय चंद्राकर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पटल पर रखा. बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस सरकार को सिंडिकेट चला रहे हैं, संविधानेत्तर संस्था चला रही है. सिंडिकेट को हटाइए. छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का जनादेश है. तीन बेटियां नदी में डूबकर मर जाए, इसलिए जनादेश नहीं मिला है.

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन अभी जनवरी में हुआ था. अब फिर जुलाई में शुरू हुआ. कोई समय सीमा है. इस पर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने कहा कि क्या आपको छत्तीसगढ़ के खेलों से एलर्जी है? क्या आपको सिर्फ हेमा मालिनी और करीना कपूर चाहिए?चंद्राकर ने कहा कि पॉवर कंपनियों के ऋण को टेकओवर करने का प्रस्ताव है. ऋण 81 करोड़ का है. क्या इसके पीछे किसी प्राइवेट पार्टी को उपकृत करने की मंशा है? हाथी मारने, शेर मारने, भालू मारने का गिरोह सक्रिय है. सरकारी संरक्षण में शिकार हो रहा है.

भाजपा सदस्य ने कहा कि नशाबंदी के लिये अनुपूरक बजट में सिर्फ़ दो सौ रुपए रखा गया है. राजीव गांधी मितान योजना के लिए बीस करोड़ रुपए रखा है. 13 तारीख़ को कितने मोहल्ले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है? चुनावी साल में राजीव गांधी मितान क्लब के लिए बीस करोड़ है, लेकिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम का एलान करने का सरकार के पास समय नहीं है.सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाषण के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर को आड़े हाथ लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अजय चंद्राकर हल्के स्तर की बात कर रहे हैं. विधायकों को गलत संबोधित करते हैं.

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं कर पाई सरकारः बृजमोहन

रायपुर। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रश्न पर आज विधानसभा में खेल विभाग ने स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार पीछे साढ़े 4 सालों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा नहीं कर पाई है. साथ ही 2019, 2020-21, 2021-22 में और 2023-24 में सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि योजना का लाभ नहीं दिया है. जिस पर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा, सरकार ने खिलाड़ियों का भविष्य चौपट कर दिया है.

विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने खेल मंत्री से पूछा कि, 1 जनवरी 2019 से 25 जून 2023 तक प्रदेश में कितनी उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की गई है? कब-कब, किन-किन खेलों के लिए कितने-कितने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है. अगर नहीं किया गया है तो क्यों? इस अवधि में कितने खेलों के कितने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि योजना का लाभ दिया गया है? किस-किस वर्ष दिया गया है?जिसके जवाब में खेल मंत्री ने बताया कि, साढ़े 4 सालों में छत्तीसगढ़ में किसी भी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया है. साढ़े 4 साल से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की फाइल कार्यवाही पर है, प्रक्रियाधीन है. खेल मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि, सिर्फ 25 खेलों के 398 खिलाड़ियों को सिर्फ 2 साल ही नगद पुरस्कार राशि का लाभ दिया गया है. वर्ष 2019 में 2020-21 और 2021-22 में खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि योजना का लाभ ही नहीं दिया गया है.वहीं इस मामले को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सरकार ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का भविष्य चौपट कर दिया है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के विकास को रोक दिया है।

नग्न प्रदर्शन पर सदन गर्म, विपक्ष के 13 विधायक निलंबित

रायपुर । फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एसटी, एससी छात्रों के नग्न प्रदर्शन की गूंज विधानसभा में सुनाई दी। विपक्षी विधायकों ने शून्यकाल में कहा कि इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, ये स्थिति निर्मित क्यों है, यह बड़ा सवाल है। भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की।

सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नग्न प्रदर्शन की सूचना शासन को पहले से नहीं दी गई थी। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ नौकरी करने वालों के खिलाफ नग्न प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा रोकने पर झूमाझटकी की गई। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।शून्यकाल में सबसे पहले बसपा विधायक इंदू बंजारे ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार एसटी, एससी छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को गिरफ्तार करना समूचे समाज का अपमान है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

विधानसभा चुनाव : नोडल अधिकारियों की गई नियुक्ति दी गई जिम्मेदारियां

रायपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफलतापूर्वक संचालन के लिए स्वीप, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था, सम्पत्ति विरूपण, मतदान दल,मास्टर ट्रेनर्स, सेक्टर अधिकारी, माईकोआब्जवर का गठन, मीडिया प्रमाणणन अनुवीक्षण समिति, पेड न्यूज, वितरण/वापसी केन्द्र मे लाईट, गाईक, शमियाना, अवकाश स्वीकृति,स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, प्रेक्षको, रोक्टर अधिकारियो, उडन दस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम,बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फोटो मतदाता पर्ची वितरण, सेक्टर/रूट चार्ज, मतदान दलो की रवानगी एवं सकुशल वापसी, फ्लाईग स्क्वार्ड, स्थाई निगरानी समिति का गठन,चिकित्सा व्यवस्था, डाक मतपत्र एवं सर्विस वोटर हेतु ई.टी.पी.बी.एस. तथा निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाणपत्र, वेबकास्टिंग, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रशिक्षण, आई कार्ड जारी करना, कन्ट्रोल रूम की स्थापना, आई कार्ड जारी करना, विडियोग्राफी, कन्ट्रोल रूम/ सहायता केन्द्र, व्यय प्रेक्षक, लेखांकन दल, वीडियो निगरानी दल, कम्प्यूटर, स्कैनर,प्रिंटर, फोटोकापी मशीन आदि की व्यवस्था हेतु कुल 33 नोडल अधिकारी तथा 133 सहायक नोडल अधिकारियो की नियुक्ति कर दी है।

नवजात शिशुओं की मौत की जांच के लिए समिति गठित

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने मानसून सत्र में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से बच्चों की मृत्यु पर सवाल उठाया. इस पर जांच के लिए समिति का गठन किया गया. कौशिक ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और नवजात शिशुओं की मृत्यु को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, इस मामले को लेकर भाजपा लगातार सवाल उठाती रही है. पिछले पांच वर्षों में नवजात शिशुओं की मृत्यु को प्रदेश सरकार हमेशा से छुपाते आई है. कौशिक के सवाल पर उपमुख्यमंत्री के लिखित उत्तर में बताया गया कि पांच वर्षों में 0 से 28 दिन के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या कुल 23 हजार 693 है और 5 वर्ष से कम बाल मृत्यु की संख्या 15 हजार 574 है. कुल मिलाकर 39 हजार 267 बच्चों की मृत्यु विभिन्न अस्पतालों में हुई है. कौशिक ने कहा, भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते आई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण लागातार बच्चों की मृत्यु हो रही है. इसके बावजूद समस्याओं को सुलझाने के बजाय सरकार इस मामले को टालने का काम कर रही है.धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार केवल झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर कम हुए हैं और सुपोषण की संख्या बढ़ी है. अब सवाल यह है कि इन पांच सालों में हजारों बच्चों की जान कैसे गई. यह एक गंभीर मामला है।

लव जेहादः रफा-दफा करने हो रही है लीपापोतीः साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर के निवासियों का क्षोभ अब तक कम नहीं हुआ है। विदित रहे, श्री साव ने मंगलवार को ग्राम बिरनपुर जाकर स्व. भुनेश्वर साहू के परिजनों से सौजन्य भेंट की। श्री साव ने इस दौरान स्व. भुनेश्वर साहू के परिजनों को पार्टी की ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने परिजनों से चर्चा के बाद कहा कि भुनेश्वर साहू की जेहादियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के मामले में शोक संतप्त परिवार को समुचित न्याय नहीं मिलने के कारण बिरनपुर में अब तक क्षोभ और दुःख का वातावरण है। लव जिहाद का विरोध करने पर भुनेश्वर साहू की संप्रदाय विशेष के धर्मस्थल में जेहादियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इसके चलते ग्राम में कई दिनों तक तनाव का वातावरण रहा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपने तुष्टीकरण और धर्मांतरण के राजनीतिक एजेंडे के चलते शोक संतप्त परिवार को समुचित न्याय मुहैया नहीं कराया। श्री साव ने कहा कि इस मामले में 40 से ज्यादा नामजद आरोपी हैं लेकिन सिर्फ 11 लोगों को ही हिरासत में लिया जाकर मामले में लीपापोती की जा रही है और राजनीतिक संरक्षण देकर मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है।

कांग्रेस का एक और आदिवासी विरोधी कृत्यः लता उसेंडी

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य व पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने कहा है कि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से सांसद फूलोदेवी नेताम का इस्तीफा कांग्रेस में मचे घमासान और भगदड़ का एक और उदाहरण है। सुश्री उसेंडी ने कहा कि सत्ता और संगठन में बदलाव के नाम पर आदिवासी नेतृत्व और महिला नेतृत्व को अपमानित का जो सिलसिला कांग्रेस में चल रहा है, उसकी बड़ी कीमत प्रदेश कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार को चुकानी ही पड़ेगी। पूर्व मंत्री सुश्री उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश में आदिवासियों के प्रति अपने दुराग्रह का प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मोहन मरकाम और मंत्रिमंडल से प्रेमसाय सिंह टेकाम की छुट्टी के बाद अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से फूलोदेवी नेताम को पद से हटाया जाना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस को आदिवासियों और महिलाओं का राजनीतिक उत्कर्ष जरा भी रास नहीं आ रहा है और मौका तलाशकर उन्हें लूप लाइन में डालकर उभरते आदिवासी और महिला नेतृत्व को नेस्त-नाबूद कर रही है। सुश्री उसेंडी ने कहा कि फूलो देवी ही अब प्रदेश से राज्यसभा में इकलौती छत्तीसगढ़िया सांसद हैं जबकि शेष राज्यसभा सदस्य अन्य राज्यों के नेताओं को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ियावाद और आदिवासियों के नाम पर सियासी ड्रामे खेलती कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार का यही मूल आदिवासी और महिला विरोधी राजनीतिक चरित्र है।

भाजपा का अजा मोर्चा उतरा कार्रवाई के विरोध म

रायपुर। फर्जी सर्टिफिकेट और इन प्रमाणपत्रो के आधार पर नौकरी के विरूद्ध शिकायतों पर कार्रवाई नहीं किये जाने के विरोध में मंगलवार को एसटी-एससी के युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था। उन्होंने नग्न होकर विधानसभा कूच करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने 25 प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वही अब प्रदर्शन के बाद हुई इस पुलिस कार्रवाई पर भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा ख़ासा नाराज नजर आ रहा है। गिरफ्तारी और कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के अजा मोर्चा ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसकी अगुवाई खुद प्रदेश अजा मोर्चा के प्रमुख और पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने की है। उन्होंने पूछा है नग्न प्रदर्शन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सरकार इस पर जवाब दे। वही जो अपनी आवाज उठा रहे है उनपर कार्रवाई क्यों हो रही है? इस कार्रवाई का भाजपा विरोध करती है।गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति का मामला गर्माया हुआ है। जिसे लेकर स्ट-स्ज्ञ युवाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को युवाओं ने नग्न होकर विधानसभा मार्च किया था। विधानसभा के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही थी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का हितग्राहियों को लाभ देंः सांसद सोनी

रायपुर। सांसद श्री सुनील सोनी ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष मे जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक (विशेष डीएलआरसी) की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे छोटे व्यापारी विशेष कर स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय मदद मिलती है जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। श्री सोनी कहा कि यह कोरोना महामारी के समय प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने लाई गई थी। यह ऐसी योजना है जो समाज के निर्धन वर्ग को सशक्त बना सकती है। सभी बैंक इस योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों को दें।

श्री सोनी ने कहा बैकों के अधिकारी-कर्मचारी शिविर लगाएं और साथ ही हितग्राहियों के पास स्वयं पहुंचे और योजना की जानकारी दें, लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। यदि उन्हें फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कठिनाई होती है तो उनका समाधान करें। यह बैंक अधिकारियों की जिम्मेदारी है यदि कोई हितग्राही उनके पास आता है तो संवेदनशीलता के साथ योजनाओं और प्रक्रिया की जानकारी दें और ऋण प्रदान करें। नगर निगम के माध्यम से आए आवेदनों को रिजेक्ट न करें बल्कि हितग्राहियों से स्वयं संपर्क या मिल कर जो कमियां है उन्हे पूरी कराएं। सांसद श्री सोनी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी वयस्कों का खाता खोलने का निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवं जनधन योजना की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों को लाभ देने कहा।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे रे कहा कि बैंकिंग करेस्पान्डेंट शाम को सडकों में लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के पास पहुंचे और उन्हें इस योजना के बारे में समझाएं और सहमत होने पर फॉर्म भरवाएं। यदि पहले चरण में 10 हजार रूपये का ऋण प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हे दूसरे चरण का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं अन्य लाभ देना सुनिश्चित करें। नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि नेटबैंकिग और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में तकनीकी समस्या आ रही है।

बिलासपुर के संयुक्त संचालक शिक्षा एवं सहायक ग्रेड-2 निलंबित

रायपुर। सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर श्री एस. के. प्रसाद और तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 श्री विकास तिवारी, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय से आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय एवं श्री तिवारी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर नियत किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति पश्चात पदस्थापना ओपन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के लिए सभी संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के पालन में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर के द्वारा सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक तथा शिक्षक से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए काउंसलिंग करते हुए पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। इस काउंसलिंग के पश्चात भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश में संशोधन किए जाने के लिए लेन-देन कर संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किए जाने के निर्देश का उल्लंघन किया जाना पाया गया। इस कार्यवाही के लिए प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर एस.के. प्रसाद और तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर विकास तिवारी की संलिप्तता पाई गई।

■ शिक्षकों की पदस्थापना में गड़बड़ी के मामले में शासन ने की कार्रवाई

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.